mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-02 अंक-86 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

मनेन्द्रगढ़
29 मार्च 2026 रविवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर विमान की आपात लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक फ्लाइट ने आपात लैंडिंग की है। अग्निशमन विभाग के अनुसार, विमान सुरक्षित उतरा है और सभी यात्री भी सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से दिल्ली आ रहा था। इंजन में तकनीकी खराबी के चलते विमान की दिल्ली हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग कराई गई। इस दौरान रनवे पर फुल इमरजेंसी लागू कर दी गई थी और सभी आपात सेवाओं को तैयार रखा गया था।

विमान का इंजन फेल होने के चलते हुई आपात लैंडिंग :विमान हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि विमान का इंजन फेल हो गया था। आपात लैंडिंग करने वाले विमान में 160 यात्री सवार थे। इंडिगो की विशाखापत्तनम-दिल्ली की उड़ान 6ई 579 को इंजन फेल होने के चलते आपात लैंडिंग करनी पड़ी। यह बोइंग 737 विमान था। फ्लाइट रडार24 डॉट कॉम के अनुसार, विमान ने शनिवार सुबह 10.50 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की।

राजस्थान में आज बारिश, ओले गिरेंगे :यूपी- बिहार में भी अलर्ट

हिमाचल में बर्फबारी की संभावना, कश्मीर में एवलांच से 7 की मौत

भोपाल/लखनऊ/शिमला/देहरादून, एजेंसी। देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम में बदल रहा है। राजस्थान में शनिवार से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। इसका असर प्रदेश के सभी जिलों में रहेगा। बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 29 मार्च से लगातार 3 दिन बारिश की संभावना है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर-जबलपुर समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। हालांकि, शनिवार को प्रदेश में तेज गर्मी रहेगी।

उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को लखनऊ, कानपुर समेत 10 जिलों में रुक-रुककर बारिश हुई। अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहेगा। कहीं-कहीं ओले गिर सकते हैं। बिहार में आधी रात को पटना समेत 5 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। आज 38 जिलों में अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश में अगले छह दिन तक बर्फबारी हो सकती है।

चिंताजनक:

देश में प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई

नाइजीरिया में स्थिति सबसे भयावह

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनियाभर में माताओं के स्वास्थ्य को लेकर किए जा रहे दावों के बीच एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। भारत में मातृ मृत्यु दर की स्थिति अब भी गंभीर है। 2023 में भारत में प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई, जो दक्षिण एशियाई देशों में काफी अधिक है। प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी) 2023 के विश्लेषण में यह तथ्य सामने आए हैं। स्वास्थ्य मैट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान (आईएचएमई) के शोधकर्ताओं की ओर से तैयार रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रगति के बावजूद सुधार की दर अब असमान और धीमी हो गई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में यह आंकड़ा 10,300 रहा। नाइजीरिया में स्थिति सबसे भयावह (32,900) है।

वैसे, 1990 की तुलना में वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु दर में एक तिहाई की गिरावट आई है, लेकिन दुनिया के 204 में से 104 देश अब भी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के उस मानक को पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसमें इस आंकड़े को 70 से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य प्रणालियों को तत्काल मजबूत करने की जरूरत :शोधकर्ताओं ने कहा कि 2030 के वैश्विक लक्ष्यों (एसडीजी) को पाने के लिए अब पांच साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और निगरानी बढ़ाने के लिए नए सिरे से वैश्विक कार्यवाही और निरंतर निवेश की तत्काल आवश्यकता है, ताकि मातृ मृत्यु दर में आ रही गिरावट की गति को तेज किया जा सके।

मुख्य कारण और समाधान :विशेषज्ञों ने पाया कि प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव और गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप मौतों के सबसे बड़े कारण हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना महामारी ने टीकाकरण से पहले के दौर (2020-21) में इस संकट को और गहरा दिया था।

53 इकाइयों में जवानों व अधिकारियों का जोखिम-कठिनाई भत्ता बंद

22 से 30 हजार रुपये तक का होगा नुकसान

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की 53 इकाइयों के हजारों जवानों और अधिकारियों का जोखिम एवं कठिनाई भत्ता तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इससे उन्हें हर माह 22 से 30 हजार रुपये का नुकसान होगा। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को सीआईएसएफ मुख्यालय में कहा था कि 2019 के कार्यालय ज्ञापन ओएम के तहत जवानों-अधिकारियों को जोखिम एवं कठिनाई भत्ता दिया जा रहा, उसकी समीक्षा की जाए। यह भी कहा था कि उन्हीं कार्मिकों को उक्त भत्ता दें, जो मंत्रालय के 22 फरवरी 2019 को जारी ओएम के अनुसार योग्य हैं।सीआईएसएफ महानिदेशालय ने ओएम के तहत यह भत्ता लेने वाले कार्मिकों की समीक्षा की। इसके बाद भत्ते रोकने का निर्णय लिया गया। यह भत्ता केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों को जोखिम भरे और कठिन क्षेत्रों में काम करने को दिया जाता है। जोखिम और कठिनाई का स्तर क्षेत्रानुसार बदलता है। जिन क्षेत्रों की यूनिटों पर भत्ते रोके गए हैं उनमें सर्वाधिक झारखंड के हैं।?इनके अलावा तेलंगाना, बंगाल में कुछ यूनिटों में ये भत्ते रोके गए हैं।?

जोखिम कम होने पर हटा दिए जाते हैं भत्ते :ये भत्ते उच्च जोखिम/कठिनाई (आर1एच1), उच्च जोखिम/मध्यम कठिनाई (आर1एच2) और उच्च जोखिम/कम कठिनाई (आर1एच3) अंतर्गत दिए जाते हैं। जोखिम और कठिनाई वाले क्षेत्रों में जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित राज्य, उत्तर पूर्व के कई स्थान शामिल हैं। कई दूसरे इलाके भी सूची में हैं। जब किसी क्षेत्र में जोखिम का स्तर और कठिनाई कम होता है तो वहां पर भत्ते हटा लिए जाते हैं।

ईरान जंग में हूती विद्रोही भी शामिल: इजराइल पर 2000 किमी से बैलिस्टिक मिसाइल दागी

कहा- मकसद पूरा होने तक हमला जारी रहेगा

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। ईरान-इजराइल जंग के 28 दिन बाद अब हूती विद्रोही भी इसमें शामिल हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में मौजूद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के दक्षिणी शहर बेर्शेबा और आसपास के इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी।

इजराइली सेना के मुताबिक, मिसाइल लॉन्च का पता चलते ही एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया और खतरे को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मौजूदा जंग के दौरान यमन से इजराइल पर यह पहला हमला माना जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है। हूती समूह ने कहा कि उसका अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता।

ईरान के हमले में एक सप्ताह में 24 अमेरिकी सैनिक घायल :ईरान के हमलों में पिछले एक हफ्ते के दौरान 24 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है।

ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर शुक्रवार रात को 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागीं। इस हमले में कम से कम 15 सैनिक घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि करीब 10 सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें 2 गंभीर थे। इस हफ्ते की शुरुआत में भी इस एयरबेस पर दो बार हमले हुए थे। इनमें से एक हमले में 14 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब की राजधानी रियाद से करीब 96 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बेस सऊदी वायुसेना के नियंत्रण में है, लेकिन इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना भी करती है।

अमेरिका ने ईरान पर 850 टॉमहॉक मिसाइलें दागीं

इसे बनाने में 2 साल लगते हैं, जंग खिची तो स्टॉक खत्म होने की आशंका

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसे अमेरिकी हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चार हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4,000 टॉमहॉक मिसाइलें थीं। अगर यह सही है तो टॉमहॉक मिसाइलों का करीब एक चौथाई हिस्सा खत्म हो चुका है। रक्षा मंत्रालय के भीतर इसको लेकर चिंता बढ़ गई है।

अयोध्या में परिवहन मंत्री के यज्ञ स्थल में लगी आग

राम मंदिर से 800 मीटर दूर हादसा; 1251 कुंड के साथ पंडाल जलकर राख

अयोध्या, एजेंसी। अयोध्या में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के यज्ञ स्थल में शनिवार दोपहर 12 बजे अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते यज्ञ स्थल, जो लगभग एक एकड़ में फैला था, पूरी तरह खाक हो गया। यह हादसा 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ के पूर्ण होने के डेढ़ घंटे बाद हुआ।

आगलगी के समय यज्ञशाला खाली थी। यज्ञशाला में 1,251 हवन कुंड बने थे। अंतिम दिन, यानी पूर्णाहुति के दिन, 50 हजार से अधिक लोग जुटे थे।

यज्ञशाला में 5 हजार से अधिक यजमानों ने आहुति दी थी।

हादसा राम मंदिर से 800 मीटर दूर, सरयू तट पर स्थित बाटी बाबा के आश्रम के पास हुआ। बताया जा रहा है कि यज्ञ के पूर्ण होने के बाद एक नारियल फूटने से चिंगारी निकली, जो कपड़े से बने पंडाल में लगी। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे यज्ञस्थल को अपनी चपेट में ले ले गईं।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा- कोई जनहानि नहीं हुई है। सब नियंत्रित है। एक फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद था। उसने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया। समापन होने के डेढ़ घंटे बाद ये घटना हुई।

शाह ने ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया

बोले- इसमें टीएमसी के काले कारनामे, बंगाल का यह चुनाव देश की सुरक्षा के लिए अहम

नई दिल्ली/ गुवाहाटी/ कोलकाता, एजेंसी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। कहा- इसमें झरखंड सरकार के 15 साल के काले कारनामों का जिक्र है, ये जनता की चार्जशीट है। बंगाल अराजकता और बदहाली है।यहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। बंगाल में झूठ की राजनीति हो रही है, भय और भ्रष्टाचार झरखंड के हथियार हैं। इस बार का चुनाव देश की सुरक्षा के लिए अहम है। ममता सरकार घुसपैठियों को बचाती है। जनता BJP को चुनने का मन बना चुकी है। उधर असम के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर सिर्फ एक समुदाय की पार्टी होने का आरोप लगाया। हिमंता ने कहा कि लगभग 99 प्रतिशत हिंदू कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। राज्य में इसके टूटने का प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। नतीजों के बाद, कांग्रेस एक ही कम्युनिटी की पार्टी बन जाएगी।

गृह मंत्री ने कहा- घुसपैठियों से मुक्त बंगाली समाज की रचना के भरोसे का चुनाव है : गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह चुनाव शांति के भरोसे का है। सम्मान की जिंदगी की गारंटी का है। मुफ्त इलाज के भरोसे का है। पक्के घर के अधिकार का है। मुफ्त बिजली हर गरीब तक पहुंचाने का है। युवाओं के उज्जवल भविष्य का चुनाव है। घुसपैठियों से मुक्त एक बंगाली समाज की रचना के भरोसे का चुनाव है। और यही भरोसा बंगाल के चुनाव का मुद्दा बना है। शाह बोले- बंगाल की जनता ने तय किया है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई जाएगी अमित शाह ने कहा- इस बार बंगाल की जनता ने तय किया है कि प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। यह चुनाव, जान जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है। आजादी छिनने के भय से मुक्ति का चुनाव है। अपनी संपत्ति लुटने के भय से मुक्ति का चुनाव है। रोजगार छिनने के भय से मुक्ति का चुनाव है। महिलाओं की सुरक्षा के खतरे से मुक्ति का चुनाव है। युवाओं के भविष्य पर छाए भय और अंधकार से मुक्ति का चुनाव है।

हिमंता बोले- 99% हिंदू कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं

रिजल्ट बाद बस एक समुदाय की पार्टी बन जाएगी; शिवराज ने कहा- असम में बीजेपी की लहर

नई दिल्ली/ गुवाहाटी, एजेंसी। असम के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर सिर्फ एक समुदाय की पार्टी होने का आरोप लगाया। हिमंता ने कहा कि लगभग 99 प्रतिशत हिंदू कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। राज्य में इसके टूटने का प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। नतीजों के बाद, कांग्रेस एक ही कम्युनिटी की पार्टी बन जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुवाहाटी में कहा कि हर जगह BJP के पक्ष में जोरदार लहर है। मैं यह सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। हमें सेंचुरी (100 सीटें जीतना) लगाने का भरोसा है। असम में 9 अप्रैल को सिंगल फेज में चुनाव हैं। 30 मार्च को पीएम मोदी NaMo ऐप के जरिए एक रैली को वर्चुअली संबोधित करेंगे। राज्य BJP ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से इस अनोखी और इंटरैक्टिव पहल में हिस्सा लेने के लिए ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करने की बात कही है। असम में 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए मौजूदा BJP के नेतृत्व वाली NDA सरकार और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा।

मोदी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया:

बोले- युद्ध के संकट से देश को एकजुट होकर लड़ना है

योगी बोले- पूरी दुनिया में पेट्रोलियम के दाम आसमान छू रहे, हमारे यहां सब ठीक

सीएम योगी ने कहा कि यूपी की 25 करोड़ जनता की ओर से पीएम का हृदय से स्वागत करता हूं। कल ही रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश के अंदर उत्साह का माहौल था। पूरी दुनिया में वर्तमान में अराजकता का माहौल है। पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच की वजह से देश में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोलियम के दाम स्थिर है। आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अमेरिका जैसे देशों में पेट्रोलियम के उत्पादों की कीमत बढ़ी हुई दिख रही है। पड़ोसी देशों में भी ऐसा दिख रहा है। वहां के देशों में अव्यवस्था बन चुकी है। पब्लिक में कोटा सिस्टम लागू करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे देश में उत्पादन को बनाए रखने और एक्साइज ड्यूटी कम करने का निर्णय लिया गया। मैं इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

नोएडा, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-1 का उद्घाटन किया। यह अभी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 4 फेज पूरे होने पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से इजराइल-अमेरिका और ईरान की जंग से उपजे संकट से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा- कल सभी राज्यों के सीएम से चर्चा हुई। देशवासियों से कहूंगा कि धैर्य और एकजुटता के साथ इस संकट का सामना करें। ये पूरी दुनिया को परेशान करने वाला संकट है।

प्रधानमंत्री ने कहा- देश के राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक हैं। देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को जनता कभी माफ नहीं करेगी।

एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। इसमें करीब 3300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं। यह टर्मिनल हर साल लगभग 3 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 11 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

'पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से दुनिया के सामने संकट खड़ा हुआ' :पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। इसके चलते कई देशों में संकट पैदा हो गया है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस युद्ध-प्रभावित क्षेत्रों से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वह कदम उठा रही है, जिससे सामान्य परिवारों और किसानों पर बोझ न पड़े। 140 करोड़ देशवासी इस मुसीबत का एकजुट होकर सामना करें।

पीएम मोदी विपक्ष के लिए बोले- ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक :पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक हैं। उन्होंने कहा कि जो भारतीयों के हक में है, हित में है, वहीं भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने के लिए राजनीतिक बहस में कुछ नंबर तो पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी कुछ लोगों ने गुमराह किया, झूठ बोले, लेकिन जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया। ठुकरा दिया। मुझे भरोसा है कि देश के राजनीतिक दल इससे सबक सीखेंगे और एकजुट प्रयासों को बल देंगे, ताकत देंगे।

कमजोर बच्चों की पहचान के लिए दिल्ली सरकार चलाएगी विशेष अभियान, 1098 हेल्पलाइन नंबर के प्रति बढ़ेगी जागरूकता

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार अप्रैल में पूरे शहर में एक अभियान चलाएगी, ताकि कमजोर बच्चों की पहचान की जा सके, उन्हें वेलफेयर स्कीम से जोड़ा जा सके और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में जागरुकता बढ़ाई जा सके। महिला और बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी), नान-प्राफिट संस्थाओं के साथ मिलकर, झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में रहने वालों को मौजूद सपोर्ट सिस्टम के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाएगा। विभाग की जानकारी के अनुसार 2023 में चाइल्ड हेल्पलाइन के इमरजेंसी नंबर 112 के साथ मर्ज होने के बाद, 2023 और 2025 के बीच 2,18,699 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 14,684 मामले डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स (डीसीपीयूए) को भेजी गईं। इनमें बच्चों के साथ गलत व्यवहार की 4,249, काउंसलिंग सपोर्ट की 1,951, लापता बच्चों से संबंधित 1,984 और बच्चों और परिवार से जुड़े मामले 1,114) शामिल थे।

कभी सर्दी तो कभी गर्मी... दिल्ली-एनसीआर के मौसम को ये क्या हुआ

नई दिल्ली, एजेसी। शहर के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को सुबह के समय हल्की वर्षा दर्ज की गई। इसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई। शाम साढ़े पांच बजे तक सफदरजंग में 0.7 मिमी, लोधी रोड पर 1.2 मिमी, राजघाट और मयूर विहार दोनों जगह में 1.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते रविवार के लिए वर्षा और गरज के साथ आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि एक दिन पहले यह 34.8 डिग्री सेल्सियस था। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 72 से 41 प्रतिशत रहा।

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की उम्मीदः मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिन के तापमान में मामूली गिरावट की उम्मीद है। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट आएगी। उसके बाद के दो दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी और उसके बाद फिर से दो तीन डिग्री की गिरावट आएगी। अगले सात दिनों तक तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, सिवाय 28 और 29 मार्च के, जब तापमान सामान्य रहेगा। रविवार की सुबह हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज/बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। दोपहर से हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज/बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। सोमवार को भी हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज/बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच, वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है और यह मध्यम स्तर पर बनी हुई है। शुक्रवार को एक्यूआइ 144 था, जबकि एक दिन पहले यह 186 था, दोनों ही मध्यम श्रेणी में थे। पूर्वानुमान के अनुसार, अगले सात दिनों तक एक्यूआइ मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है।

यमुनापार में डीडीए की करोड़ों की जमीन पर माफिया का राज, अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप

पूर्वी दिल्ली, एजेसी। यमुनापार में डीडीए की खाली पड़ी करोड़ों रुपयों की जमीनों पर माफिया का कब्जा चल रहा है। कहीं पर सरकारी जमीनों को कबाड़ियों ने घेरा हुआ है तो कहीं पर झुग्गियां बसाकर लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डीडीए को इसकी भनक नहीं है। आम लोग तो छोड़िए सत्ता में बैठे विधायक तक दिल्ली विधानसभा आरोप लगा रहे हैं कि डीडीए के अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। वह जमीनों को खाली करवाने के लिए डीडीए से कह कहकर थक गए हैं। गाजीपुर, विश्वास नगर, कड़कड़डूमा, गौतमपुरी, न्यू अशोक नगर, मयूर विहार, कोंडली, हर्ष विहार, सुंदर नगरी समेत कई क्षेत्रों में डीडीए की जमीनों पर कब्जा है। गाजीपुर पेपर मार्केट के पास डीडीए की जमीन पर करीब सौ से अधिक झुग्गियां बसाकर लोग रह रहे हैं। इसमें अधिकतर वह लोग रह रहे हैं तो दिहाड़ी मजदूर हैं। कड़कड़ी मोड़ के पास डीडीए की जमीन पर ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन चल रहा है, यहां तो बकायदा डीडीए का बोर्ड भी लगा हुआ है। इसके बाद भी माफिया जमीन पर कब्जा करके चार्जिंग स्टेशन चला रहे हैं। चार्जिंग के लिए दूर से तारों की लाइन बिछाई हुई है। एक रिक्शा चार्जिंग के सौ रुपये वसूले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जे का खेल चल रहा है। माफिया कब्जा करने की एवज में अधिकारियों से मोटी रकम देते हैं। यही वजह है कि सरकारी जमीन पर कब्जा होने के बाद भी अधिकारी उसे खाली नहीं करवा पा रहे हैं। कड़कड़डूमा गांव में डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से पार्किंग चल रही है। डीडीए की दीवार भी जगह-जगह से टूटी पड़ी है। यहीं से कुछ ही दूरी पर डीडीए की दूसरी जमीन पर नर्सरी चल रही है। रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन ने दिल्ली विधानसभा में सरकारी जमीनों पर कब्जे का मुद्दा रखा। इसके साथ ही कहा कि डीडीए के अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं।

प्राकृतिक उपायों से बालों को जड़ों से कर सकते हैं मजबूत

नई दिल्ली, एजेसी। आयुर्वेद के अनुसार बालों का स्वास्थ्य केवल बाहरी देखभाल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह शरीर के आंतरिक संतुलन, पोषण और जीवनशैली का भी परिणाम होता है। इसलिए प्राकृतिक उपायों को अपनाकर बालों को जड़ों से मजबूत किया जा सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जिनसे बने तेल बालों को गहराई से पोषण देते हैं। एक आसान घरेलू उपाय में आंवला चूर्ण, कड़ी पत्ता, नारियल तेल और मेथी दाना को धीमी आंच पर पकाकर तेल तैयार किया जाता है। जब तेल का रंग हल्का बदलने लगे और उसमें सुगंध आने लगे, तब इसे छानकर कांच के बर्तन में रख लिया जाता है।

टेल्मिसार्टन सहित कई बीपी दवाएं गुणवत्ता टेस्ट में फेल, मरीजों के लिए बढ़ा 'साइलेंट' खतरा

नई दिल्ली, एजेसी। पूरे देश में, 'टेल्मिसार्टन' हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के कई ब्रांड और बैच सरकारी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। भारत सरकार के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग कंपनियों द्वारा बनाई गई ब्लड प्रेशर की दवाओं में क्वालिटी से जुड़ी कमियां (खास तौर पर, 'घुलने में विफलता ') पाई गई हैं। इससे यह खतरा पैदा हो गया है कि मरीज़ों का ब्लड प्रेशर बिना किसी लक्षण या चेतावनी के अनियंत्रित रह सकता है।

आधिकारिक जांच में, टेल्मिसार्टन के कई ब्रांड और बैच 'स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं' पाए गए। नतीजतन, पूरे देश में एक बढ़ते, खामोश स्वास्थ्य खतरे जो बिना किसी स्पष्ट संकेत के सामने आता है, उसको लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं। जांच से पता चला कि जहां अलग-अलग कंपनियां इस दवा को अलग-अलग ब्रांड नामों से बनाती हैं, वहीं लगभग दस अलग-अलग दवा निर्माताओं के प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। इन दवाओं में पाई गई सबसे बड़ी कमी 'घुलने में विफलता' थी। एक ऐसी स्थिति जिसमें दवा शरीर के अंदर ठीक से घुल नहीं पाती है। इसके परिणामस्वरूप, दवा की असरदारता या तो काफी कम हो जाती है या वह पूरी तरह से बेअसर हो जाती है। कुछ मामलों में, जांच में 'एसे विफलता' (एक ऐसी स्थिति जहां दवा में मौजूद असली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट तय मानक से कम होता है या पूरी तरह से गायब होता है) भी सामने आई। खास बात यह है कि यह समस्या सिर्फ टेल्मिसार्टन तक ही सीमित नहीं है; रिपोर्ट बताती है कि ब्लड प्रेशर की अन्य दवाओं–जैसे एनालाप्रिल, एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल और लैबेटालोल के बैच भी टेस्टिंग के दौरान क्वालिटी मानकों को पूरा करने में फेल रहे। यह साफ है कि यह समस्या किसी एक कंपनी की दवा तक सीमित नहीं है, बल्कि कई निर्माताओं द्वारा बनाए गए दवाओं के बैचों को प्रभावित करती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि मरीज़ों को कोई संकेत नहीं मिलता कि उनकी दवा बेअसर है। न तो कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, और न ही कोई तत्काल शारीरिक बदलाव होते हैं जो मरीज़ को सचेत कर सकें। हालांकि, इन दवाओं का लगातार इस्तेमाल करने के बावजूद, मरीज़ का ब्लड प्रेशर अनियंत्रित ही रहता है। इससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है।

क्या कार्रवाई की गई है, और कैसे : नियमों के अनुसार, क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए दवाओं के बैचों को बाज़ार से वापस मंगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित कंपनियों से स्पष्टीकरण माँगे गए हैं; यदि उनकी कोई गलती साबित होती है, तो लाइसेंस रद्द करने, उत्पादन पर रोक लगाने या अन्य कानूनी कार्रवाई जैसी कदम उठाए जाएँगे। फ़िलहाल, इस मामले से जुड़ी नियामक प्रक्रिया चल रही है।

मरीजों के लिए सलाह : इस मामले को देखते हुए, छ्ष्ठस्ष्ह्र और चिकित्सा विशेषज्ञों ने मरीज़ों को सलाह दी है कि वे दवाएँ केवल भरोसेमंद फ़ार्मेसी से ही खरीदें, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट की जाँच करें, और नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर की निगरानी करते रहें।

विधानसभा में 'फांसी-घर' विवादः केजरीवाल सहित आप नेताओं को विशेषाधिकार समिति की चेतावनी

नई दिल्ली, एजेसी। दिल्ली विधानसभा ने फांसी-घर मामले को लेकर मामले में दो बार बुलाए जाने पर पेश न होने की विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष पदुम्न राजपूत द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को चेतावनी जारी की। इस मामले पर सदन में लाए गए भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन के प्रस्ताव पर बहस हुई।

महाजन ने समिति के समक्ष पेश होने न होने को अवमानना मानकर केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं को चेतावनी जारी करने की सिफारिश की। भाजपा के विधायक राजकुमार भाटिया ने प्रस्ताव का समर्थन किया और अंततः इसे सदन में ध्वनिमत के जरिए पारित कर दिया गया। केजरीवाल ने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और उपाध्यक्ष राखी बिरला की मौजूदगी में नौ अगस्त 2022 को विधानसभा में फांसी-घर का उद्घाटन किया था। पिछले साल फरवरी में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने वाली जगह के बजाय टिफिन रूम बताया। इसके बाद मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजा गया। समिति ने केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया हालांकि, इस महीने के शुरुआत में केजरीवाल, गोयल व बिरला समेत आप के अन्य नेता समिति के समक्ष पेश हुए। विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि नियमों के तहत समिति के पास अवमानना के लिए जेल की सजा देने का अधिकार है, लेकिन समिति ने उचित कार्रवाई करते हुए दंड को केवल चेतावनी तक सीमित रखा है।

लोक लेखा समिति के सुझाव सदन ने स्वीकार किएः दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए तीन रिपोर्टों के निष्कर्ष को सदन ने स्वीकार कर लिया है। इनमें आबकारी नीति मामला घोटाला, स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण से संबंधित कैग रिपोर्ट के निष्कर्ष शामिल हैं। गत विधानसभा सत्र में आप सरकार के समय की ये तीनों रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई थीं। जिसके बाद सदन ने इन रिपोर्ट पर अपने निष्कर्ष देने के लिए लोक लेखा समिति को अंतिम जांच के लिए भेज दिया था। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अजय महावर ने बताया कि समिति ने तीनों मामलों में अपने सुझाव दिए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, उसको लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। पूर्व में हुए घोटाले पर भी समिति ने कार्रवाई के लिए सदन को अपने निष्कर्ष दिए हैं। जिसको सदन में स्वीकार कर लिया है। अब आगे कार्रवाई सदन द्वारा तय की जाएगी। इस उन्होंने बताया कि आबकारी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप हैं। दिल्ली विधानसभा में सदन में प्रस्तुत की गई कैग की सभी छह रिपोर्ट को जांच के लिए लोक लेखा समिति के पास जांच के लिए भेज दिया है। इनमें जल बोर्ड सहित अन्य रिपोर्ट भी शामिल है। समिति जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

दिल्ली में डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद, नाबालिग की चाकू मारकर हत्या

बाहरी दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के रानी बाग इलाके में शुक्रवार की देर रात एक शादी समारोह के दौरान गाना बजाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चाकूबाजी की इस घटना में साढ़े 17 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने कुछ नाबालिगों समेत सात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात शादी समारोह में दो पक्षों के युवकों के बीच अपनी-अपनी पसंद का गाना डीजे पर चलाने को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और एक पक्ष ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में नाबालिग के सीने में चाकू लगा, जबकि उसके साथी सनी को कमर के नीचे चोट आई। दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एसीपी, एसएचओ और क्राइम टीम मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर संदिग्धों की पहचान की गई।

रोहिणी के रहने वाले हैं मृतक : पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक और घायल युवक रोहिणी के नाहरपुर इलाके के रहने वाले हैं। मृतक मोटर मैकेनिक का काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देर रात तक चली छापेमारी में कुछ नाबालिगों समेत सात लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। फरार अन्य आरोपितों का पुलिस पता लगा रही है।

अमेरिकी सांसदों ने अंतरिक्ष और परमाणु खतरों के बढ़ने की चेतावनी दी

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सांसदों और सैन्य कमांडरों ने चेतावनी दी कि चीन, रूस और अन्य विरोधियों से बढ़ते खतरे रणनीतिक परिदृश्य को तेजी से बदल रहे हैं। भविष्य के किसी भी संघर्ष में अंतरिक्ष एक अग्रिम मोर्चे के क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई की शुरुआत करते हुए सीनेटर रोजर विकर ने कहा कि प्रतिद्वंद्वियों की प्रगति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को 'अपनी रणनीतिक क्षमताओं को मूल रूप से अद्यतन करना' होगा। उन्होंने कहा कि रूस और चीन ने परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में 'तेजी से बड़ी प्रगति' की है, जबकि उत्तर कोरिया अपने मिसाइल भंडार का विस्तार जारी रखे हुए है। अमेरिकी स्पेस कमांड के कमांडर जनरल स्टीफन व्हाइटिंग ने कहा कि विरोधी ऐसी क्षमताएँ विकसित कर रहे हैं जो 'हमें अंतरिक्ष के उपयोग से वंचित कर सकती हैं।' उन्होंने चेतावनी दी कि चीन का उपग्रह बेड़ा तेजी से बढ़ा है। उन्होंने विधायकों से कहा, 'चीन की कक्षा में उपस्थिति तेजी से बढ़ी है और अब वह 1300 से अधिक सक्रिय उपग्रह संचालित कर रहा है...जिनमें 510 से अधिक खुफिया, निगरानी और टोही उपग्रह शामिल हैं। ' उन्होंने कहा कि बीजिंग अपनी सेनाओं में अंतरिक्ष-आधारित क्षमताओं को एकीकृत कर रहा है, जिससे वे 'अधिक घातक, सटीक और दूरगामी' बन रही हैं। साथ ही, वह ऐसे हथियार भी तैनात कर रहा है जो अमेरिकी उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। इस बीच, रूस भी विघटनकारी अंतरिक्ष क्षमताओं पर काम कर रहा है, जिसमें परमाणु एंटी-सैटेलाइट हथियार की संभावित तैनाती शामिल है। व्हाइटिंग ने चेतावनी दी कि ऐसा सिस्टम 'अंधाधुंध' होगा और निम्न पृथ्वी कक्षा में सभी उपग्रहों को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कहा, 'यदि इसे कक्षा में विस्फोट किया गया, तो यह तुरंत हर देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को जोखिम में डाल देगा। '

अमेरिकी स्ट्रैटेजिक कमांड के प्रमुख एडमिरल रिचर्ड कैरोल ने व्यापक चुनौती को तेज तकनीकी बदलाव के बीच 'एक साथ कई परमाणु प्रतिद्वंद्वियों को रोकने' के रूप में बताया। उन्होंने साइबर खतरे, काउंटर-स्पेस क्षमताओं और उन्नत मिसाइल प्रणालियों को प्रमुख जोखिम क्षेत्र बताया।

मध्य पूर्व पर अमेरिका का फोकसः हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए बढ़ सकती हैं चुनौतियां

वाशिंगटन, एजेंसी। खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष अमेरिका की इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) रणनीति को कमजोर कर सकता है। इससे भारत जैसे देशों की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका का ध्यान और सैन्य संसाधन एशिया से हटकर खाड़ी की ओर जा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने यह चेतावनी दी है। एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि इस संकट का असर अब अमेरिका की अन्य क्षेत्रों, खासकर एशिया से जुड़ी योजनाओं पर दिखने लगा है, जहां अमेरिका चीन के खिलाफ अपनी ताकत मजबूत करना चाहता था। दूसरे पूर्व अधिकारी ने भी माना कि इसका असर साफ दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका के सैन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने अपने कई अहम संसाधन, जैसे वायु रक्षा प्रणाली, पहले ही खाड़ी क्षेत्र में भेज दिए हैं। इनमें से कई सिस्टम एशिया से हटाकर वहां लगाए गए हैं। अधिकारी ने कहा, 'अभी इस क्षेत्र में हमारी लगभग सभी हवाई रक्षा प्रणालियां मौजूद हैं, और उनमें से कई एशिया से ही लाई गई हैं। ' ये टिप्पणियां नई दिल्ली सहित एशियाई राजधानियों में एक बड़ी चिंता को उजागर करती हैं कि मध्य पूर्व में लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष इंडो-पैसिफिक पर अमेरिका के ध्यान को कम कर सकता है। अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस तरह के बदलावों का अक्सर लंबे समय तक असर रहता है। उन्होंने बताया कि एक बार सेना की तैनाती बदल दी जाए, तो उसे जल्दी वापस नहीं लाया जाता उन्होंने कहा, 'स्थिति को संभालने में काफी लंबा समय लग सकता है, और इसके लिए अमेरिका को उस क्षेत्र में लंबे समय तक अपनी सेना रखनी पड़ेगी।' अधिकारी ने पुराने उदाहरण देते हुए बताया कि पहले भी संकट के समय जो सैन्य बल भेजे गए थे, वे बाद में भी लंबे समय तक वहीं बने रहे। दूसरे अधिकारी ने कहा कि समय के साथ इसका असर वैश्विक स्तर पर दिखेगा और अमेरिका की अन्य क्षेत्रों में तैयारी भी प्रभावित हो सकती है।

उन्होंने कहा, 'सिर्फ पैसा इस समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि इसमें समय और भौतिक सीमाओं की भी चुनौती है। ' सैन्य संसाधनों के अलावा, यह संकट अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान भी अपनी ओर खींच रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे एशिया से जुड़े रणनीतिक फैसलों की रफ्तार धीमी हो सकती है।

अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने पर दिया जोर

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के वरिष्ठ विधायकों और अधिकारियों ने पाकिस्तान के साथ अधिक गहरे और परिणाम-उन्मुख संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है और इस रिश्ते को 'जटिल' बताया है। कैपिटल हिल पर बुधवार को टाम सुओजी और जैक बर्गमैन द्वारा आयोजित एक द्विदलीय संगोष्ठी में 200 से अधिक नीति-निर्माताओं, राजनयिकों और विशेषज्ञों ने अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों की दिशा का आकलन किया। सुओज़ी ने कहा, 'ऐसे समय में जब हमारा देश और दुनिया बढ़ती विभाजन की भावना महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान अपने संबंधों को मजबूत करना पहले से कहीं अधिक जरूरी है।' संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध जटिल रहे हैं। बर्गमैन ने विभाजनों के पार संवाद और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'ऐसी एकता संयोग से नहीं होती। यह बातचीत से शुरू होती है। यह इस साझा विश्वास से शुरू होती है कि जब लोग साथ आते हैं, खुले तौर पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और सम्मानपूर्वक जुड़ते हैं, तो प्रगति संभव है।' उन्होंने जोड़ा कि स्थायी प्रगति के लिए असहमतियों को 'सम्मान के साथ' संभालना आवश्यक है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने इस रिश्ते को दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान का यह संबंध निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संबंधों में से एक है, जो लगभग आठ दशकों में कई सफल साझेदारियों के रूप में सामने आया है। हर बार जब हम साथ आए हैं, इसका प्रभाव द्विपक्षीय दायरे से परे रहा है और पूरी दुनिया को लाभ हुआ है।

' अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव एस पॉल कपूर ने कहा कि वाशिंगटन ठोस परिणाम चाहता है। 'हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमेरिका-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों में सद्भावना और उच्च-स्तरीय ध्यान अमेरिकी और पाकिस्तानी लोगों के लिए ठोस लाभ में बदलें। ' इस संगोष्ठी में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर पैनल चर्चाएं हुईं। विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय स्थिरता, जिसमें भारत व चीन के साथ पाकिस्तान के संबंध भी शामिल हैं और व्यापार व निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया। माइकल कगलमैन (अटलांटिक काउंसिल) ने कहा कि यह साझेदारी 'अच्छी स्थिति में है,' लेकिन इसे समय के साथ अधिक टिकाऊ बनाने की जरूरत है। पूर्व राजदूत तौकीर हुसैन ने चेतावनी दी कि अमेरिकी नीति केवल दिखावे से आगे बढ़नी चाहिए। 'अगर अमेरिका अच्छे साझेदार चाहता है, तो उसे अच्छी नीतियां बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी नीति का मापदंड केवल यह नहीं होना चाहिए कि वह वाशिंगटन में अच्छी दिखती है। सुरक्षा चिंताएं भी प्रमुख मुद्दा रहीं।

लीसा कर्टिस ने चेतावनी दी कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) अब भी 'एक खतरनाक और घातक संगठन' है और पाकिस्तान की स्थिरता सुनिश्चित करने में अमेरिका की रुचि पर जोर दिया। हसन अब्बास ने आतंकवाद, संगठित अपराध और सीमा-पार खतरों से निपटने के लिए नागरिक कानून-प्रवर्तन को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। आर्थिक मोर्चे पर सोफयां युसूफी ने पाकिस्तान में डिजिटलीकरण और व्यापक आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ते प्रयासों का उल्लेख किया लेकिन निर्यात और विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए स्पष्ट औद्योगिक नीति की जरूरत बताई। एसपेरेंजा (यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स) ने कहा कि नए सिरे से जुड़ाव ने निजी क्षेत्र के निवेश के अवसर खोले हैं और द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों को सुलझाने का आह्वान किया। अंत में सुओज़ी ने कहा, 'यह सम्मेलन अतीत से सीखने, वर्तमान को समझने और हमारे दोनों देशों के बीच अधिक समझदारी व सहयोगपूर्ण भविष्य का मार्ग तैयार करने के बारे में है। '

भूकंप एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के दूसरे दिन भी दिखा उत्साह

प्रशिक्षकों व प्रतिभागियों को बचाव, राहत और त्वरित प्रतिक्रिया की दी गई जानकारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में आयोजित पांच दिवसीय भूकंप पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे दिन का प्रशिक्षण पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, संजय गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य संभावित प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर भूकंप की स्थिति में प्रभावी बचाव एवं राहत कार्यों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है प्रशिक्षण कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, छात्र-छात्राएं, विभिन्न शासकीय एवं निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, एसडीईआरएफ, एनसीसी और एनएसएस के

कैडेट्स सहित 110 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया इस दौरान प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन की मूल अवधारणाओं, भूकंप के दौरान तथा उसके पूर्व और बाद में किए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई विशेषज्ञों ने बताया कि सतर्कता, सही जानकारी और त्वरित निर्णय क्षमता से आपदा के समय जन-धन की हानि को कम किया जा सकता है। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन से संबंधित उपकरणों का लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी किया गया। प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार, सुरक्षित निकासी और समन्वित राहत कार्यों की प्रक्रिया से अवगत कराया गया यह प्रशिक्षण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से एडीएम बी.पी. पांडेय एवं एसडीएम राकेश शुक्ला के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम का संचालन नोडल अधिकारी एल.बी. कोल एवं सहायक नोडल अधिकारी मयंक तिवारी द्वारा किया गया प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों को अध्ययन सामग्री वितरित की गई तथा स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रशिक्षण में भाग लिया जिससे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

3452 बैगा महिलाओं को नहीं 1500 रुपए, एक साल पहले भरवाए जा चुके फॉर्म

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए शुरू की गई आहार अनुदान योजना सवालों के घेरे में है मध्य प्रदेश शासन ने अक्टूबर 2023 में बैगा और सहरिया परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने ?1500 देने का आदेश जारी किया था हालांकि डेढ़ साल बीतने के बाद भी इस योजना का लाभ किसी भी पात्र महिला तक नहीं पहुंच पाया है। बैगा समाज संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर बैगा ने आरोप लगाया है कि शासन ने आदेश तो जारी कर दिया लेकिन प्रशासन ने इसे लागू करने में लापरवाही बरती है। उन्होंने बताया कि कुसमी क्षेत्र सहित पूरे सीधी जिले में पंचायतों के माध्यम से महिलाओं के आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे पर आज तक किसी भी लाभार्थी को एक रुपया भी नहीं मिला बैगा ने यह भी बताया कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे से अवगत कराया है हाल ही में जिले के दौरे पर आए राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया था लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है उनके अनुसार, यह योजना केवल कागजों में ही चल रही है और जमीनी स्तर पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है ग्रामीण महिलाओं ने भी अपनी परेशानी साझा की। ग्राम छलवारी की शांति बैगा, बकवा की रामबाई बैगा, ठाडीपाथर की बसंती बैगा और समितियां बैगा ने बताया कि लगभग एक साल पहले पंचायत में उनके फॉर्म भरवाए गए थे। उन्हें हर महीने 1500 मिलने का आश्वासन दिया गया था लेकिन आज तक एक भी किस्त नहीं मिली है उन्हें यह भी नहीं बताया जा रहा कि भुगतान क्यों रुका हुआ है। प्रशासन इस मामले में निर्देशों के अभाव की बात कह रहा है। कुसमी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि आदिवासी विकास विभाग द्वारा पंचायतों से बैगा परिवार की महिला मुखियाओं की जानकारी मांगी गई थी जिसे उपलब्ध करा दिया गया है। कुल 3452 महिलाएं पात्र पाई गई हैं, लेकिन विभाग से अभी तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश या लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

कलेक्टर ने की राजस्व कार्यों की समीक्षा;प्रकरणों के जल्द निराकरण, किसान पंजीयन सत्यापन पर फोकस

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। कलेक्टर गौरव बैनल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की इस दौरान उन्होंने नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरणों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कई तहसीलों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर दिया इसका उद्देश्य आम नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना है उन्होंने उपखंड अधिकारियों को अपने अधीनस्थ तहसील न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए साथ ही स्वामित्व योजना, फार्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान योजना के तहत सत्यापन व ई-केवाईसी कार्यों

में तेजी लाने को कहा गया राजस्व वसूली के लक्ष्यों को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। किसान पंजीयन और गिरदावली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सरसों और मसूर फसलों के पंजीयन का पुनः सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपार्जन केंद्रों पर अवैध बिक्री रोकने, सीमावर्ती क्षेत्रों से फसल की आवाजाही पर निगरानी रखने और चेक पोस्ट स्थापित करने के आदेश दिए। केंद्रों पर किसानों के लिए छाया, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा गया बैठक में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनाए रखने और इनकी कालाबाजारी रोकने के निर्देश भी दिए गए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने पर भी जोर दिया गया। इस बैठक में वरिष्ठ राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।

टंसार में वृहद विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, संकल्प से समाधान अभियान के तहत योजनाओं का लाभ, निःशुल्क विधिक सहायता पर जोर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विकासखंड कुसमी के पीएम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टंसार में वृहद विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया शिविर का उद्देश्य ग्रामीण एवं विशेष रूप से आदिवासी समुदाय को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें न्याय व्यवस्था से जोड़ना रहा शिविर में उपस्थित जनसमूह को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत पीड़ित प्रतिकर योजना सहित विभिन्न विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई साथ ही संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों का मौके पर निराकरण करते हुए हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रयाग लाल दिनकर ने कहा कि जागरूक समाज ही मजबूत न्याय व्यवस्था की नींव है उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए माताओं से बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने की अपील की उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य प्रकरणों का त्वरित, सरल एवं कम खर्च में निराकरण संभव है साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली सहायता की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। न्यायाधीश ने कहा कि नशा सामाजिक एवं पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण है और इससे दूर रहना आवश्यक है।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का संबोधनः विधायक धौहनी कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि ऐसे शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम हैं। कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी का दायित्व है कि योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ आमजन तक पहुंचे। उन्होंने एक माह बाद फॉलो-अप शिविर आयोजित करने की जानकारी दी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश शिवहरे ने बताया कि प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है और इसके लिए प्राधिकरण सदैव तत्पर है।

हितलाभ वितरणः शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। स्वयं सहायता समूहों को ऋण, मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड, संबल योजना के तहत सहायता राशि, लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

स्वास्थ्य एवं विभागीय स्टॉलः कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों को जांच एवं उपचार की सुविधा प्रदान की गई।

निगाही खदान में आग का वीडियो वायरल,एनसीएल ने बताया पुराना, सोशल मीडिया पर ताजा घटना का दावा

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एनसीएल) की निगाही कोयला खदान से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में खदान के अंदर कोयले के बड़े स्टॉक में आग भड़कती दिख रही है सोशल मीडिया यूजर्स इसे ताजा घटना बताकर एनसीएल को भारी नुकसान होने का दावा कर रहे हैं वहीं एनसीएल प्रबंधन ने इसे पुराना वीडियो बताया है। करीब तीन मिनट के इस वीडियो में आग का दायरा काफी बड़ा नजर आ रहा है जिससे स्थिति भयावह लग रही है। वीडियो में कहीं भी आग बुझाने के इंतजाम या फायर सेफ्टी टीम सक्रिय नजर नहीं आ रही है। यह वीडियो शनिवार को सामने आया है।

देवी मंदिर के बाहर मारपीट,महिलाओं और युवकों ने मिलकर दो लड़कों पीटा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। अमिलिया थाना क्षेत्र के ग्राम घोघरा में एक दिन पहले अचानक माहौल बिगड़ गया देवी मंदिर परिसर के बाहर दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई इस मारपीट का वीडियो शनिवार को सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई जब लोग मंदिर में दर्शन करके बाहर निकल रहे थे वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिलाएं और युवक मिलकर दो लड़कों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं इस दौरान लात-घूंसों के साथ-साथ लाठी-डंडों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया है स्थानीय निवासी अमर सिंह ने बताया कि विवाद इतना अचानक बढ़ा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। घटना के बाद आरोपी मौके से ऑटो में सवार होकर भाग निकले मारपीट के दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं के बीच अफरा-तफरी मच गई थी ।

रामनवमी पर निःशुल्क 'जल मंदिर' (प्याऊ) का उद्घाटन

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनसेवा और जल संरक्षण का संदेश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। ग्रीष्म ऋतु में बढ़ती गर्मी को देखते हुए आमजन एवं राहगीरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में निःशुल्क 'जल मंदिर' (प्याऊ) स्थापित किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नवांकुर संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्याऊ संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रामनवमी के पावन अवसर पर वार्ड क्रमांक 07 स्थित हनुमान मंदिर परिसर में रश्मि दिव्यांग सेवा समिति द्वारा निःशुल्क जल मंदिर (प्याऊ) का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शासी निकाय सदस्य कृष्णकांत द्विवेदी एवं अध्यक्षता जिला समन्वयक मुकेश गौर ने की कार्यक्रम के दौरान वृक्ष पूजन, हनुमान चालीसा पाठ एवं जनजागरूकता से जुड़े विभिन्न आयोजन किए गए मुख्य अतिथि ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है 'जल शक्ति से जन भक्ति' की भावना से प्रेरित यह पहल न केवल जनसुविधा प्रदान करती है, बल्कि समाज में सेवा और सहयोग की भावना को भी मजबूत करती है अध्यक्षता कर रहे जिला समन्वयक ने बताया कि जल संरक्षण के क्षेत्र में नवांकुर संस्थाएं, प्रस्फुटन समितियां एवं सीएमसीएलडीपी के छात्र-छात्राएं सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के प्रयासों से जल स्त्रोतों का संरक्षण एवं जल स्तर में सुधार संभव होगा कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

अवैध पेट्रोल बिक्री विवाद में वृद्ध पर हमला; मोरवा में दो लोगों पर केस दर्ज, घायल की हालत गंभीर

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। मोरवा थाना क्षेत्र में अवैध पेट्रोल बिक्री को लेकर हुए विवाद में एक वृद्ध पर हमला किया गया। हुई इस घटना में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। यह घटना खिरवा के भोजी चौराहे के पास हुई जहां कई छोटी दुकानों में अवैध रूप से पेट्रोल बेचा जाता है जानकारी के अनुसार, सूरजमन साकेत नामक वृद्ध पेट्रोल खरीदने एक दुकान पर पहुंचे थे इसी दौरान पेट्रोल की मात्रा को लेकर उनका विवाद शुरू हो गया। मौके पर मौजूद अक्षय कोल और राकेश कोल ने विवाद को आगे बढ़ाया और सूरजमन से झगड़ा किया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आरोपियों ने वृद्ध पर पत्थर से हमला कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए वहीं दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल सूरजमन को तत्काल मोरवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। मोरवा थाना प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में दोनों आरोपी अक्षय कोल और राकेश कोल के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है।

कुसमी तहसील न्यायालय कलेक्टर ने किया निरीक्षण

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और समयबद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर विकास मिश्रा ने तहसील न्यायालय कुसमी का निरीक्षण कर न्यायालयीन एवं राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और कार्यों में गति लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों के लंबित रहने से अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते हैं इसलिए इनका त्वरित और पारदर्शी समाधान आवश्यक है। कलेक्टर ने न्यायालयों में नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि न्यायालयीन कार्यों को सर्वोच्च

प्राथमिकता दी जाए उन्होंने सभी प्रकरणों में समयबद्ध कार्रवाई कर आमजन को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राहत से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता बरतने की बात कहते हुए पात्र हितग्राहियों को बिना विलंब सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए साथ ही राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए 31 मार्च से पहले निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने तहसील परिसर का अवलोकन कर साफ-सफाई बनाए रखने और कार्यालयीन अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन से कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है। इस अवसर पर तहसीलदार नारायण सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

बिजली कर्मचारियों पर हमला, मारपीट के बाद कर्मचारियों ने काम बंद करने की चेतावनी दी

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। बैढ़न क्षेत्र में देर शाम बिजली सुधार कार्य के दौरान कर्मचारियों पर हमला किया गया इस दौरान उनके साथ मारपीट हुई और उनके वाहन में तोड़फोड़ की गई। गर्मी बढ़ने के साथ ही क्षेत्र में बिजली फाल्ट की समस्या बढ़ रही है एक शिकायत मिलने पर बिजली विभाग की टीम कचनी इलाके में सुधार कार्य के लिए पहुंची थी। कर्मचारी जैसे ही फाल्ट सुधारने में लगे कुछ स्थानीय लोग मौके पर आ गए उन्होंने गाली-गलौज करते हुए विवाद शुरू कर दिया देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई की। हमलावरों ने कर्मचारियों के वाहन में भी जमकर तोड़फोड़ की स्थिति बिगड़ती देख कर्मचारी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले और सीधे कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के बाद बिजली कर्मचारियों में भारी आक्रोश है उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे काम बंद करने को मजबूर होंगे कर्मचारियों ने यह भी बताया कि इसी क्षेत्र में पहले भी उनके साथ इस तरह के विवाद हो चुके हैं। बैढ़न थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने इस मामले पर जानकारी दी।

देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, भारत पर ईरान का रुख भी साफ, बस अफवाहों से बचें

संपादकीय

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत सरकार ने जनता भरोसा दिलाया है कि देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। भारत के पास पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। अगर सभी लोग अफवाहों से दूर रहें, जरूरत भर ही खरीदारी करें तो किसी भी कृत्रिम संकट को टाला जा सकता है।सरकार ने जनता को फिर भरोसा दिलाया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसद की कोई कमी नहीं है। भारत के पास पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। मौजूदा हालात में लोगों के बीच पनप रहे डर और आशंकाओं को देखते हुए इस तरह के भरोसे की जरूरत है।सप्लाई रुकी नहीं। गुरुवार को देश के कई शहरों से तस्वीरें आई, जहां पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें दिखीं। इस पैनिक की वजह अफवाहें और कुछ हद तक कालाबाजारी भी है। ईरान युद्ध ने बेशक ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर डाला है, लेकिन यह पूरी तरह से रुकी नहीं है। फिर भारत के पास अपना रिजर्व भी है, जो सरकार के मुताबिक 60 दिनों के लिए पर्याप्त है। साथ ही अगले दो महीने के क्रूड की खरीद पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है और रसद का घरेलू उत्पादन भी 40% बढ़ चुका है।ईरान का रुख । भारत अपने तेल आयात में लगातार विविधता ला रहा है और इस समय भी 41 से ज्यादा देशों से खरीद हो रही है। इसका मतलब है कि देश पूरी तरह से पश्चिम एशिया पर निर्भर नहीं है। फिर, भारत के कुछ वेसल को ईरान ने होर्मुज से निकलने भी दिया है। तेहरान का यह कहना भी सकारात्मक संदेश है कि भारत जैसे मित्र देशों के जहाज होर्मुज से निकल सकते हैं।भरोसा बनाए रखें । जंग में कई तरह की खबरें आती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी सही हों। कुछ का मकसद होता है अफरातफरी पैदा करना। मुनाफाखोर इसी की ताक में रहते हैं। अभी जो माहौल बन रहा है, वह भी अफवाहों और आधी-अधूरी खबरों की देन है। सरकार ने लोगों से संकट के लिए तैयार रहने को जरूर कहा है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि देश गंभीर ऊर्जा संकट से घिर चुका है। घबराने की बजाय जरूरत है कि भरोसेमंद माध्यमों से मिलने वाली खबरों पर ही यकीन किया जाए और मुनाफाखोरों-कालाबाजारी करने वालों को कोई मौका न दिया जाए।असली परीक्षा। अमेरिका-इस्राइल और ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया के ही सामने चुनौती पेश की है। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है। इसलिए इस युद्ध से भारत भी अछूता नहीं रह सकता। इस सच को स्वीकार करने के साथ यह भी समझने की जरूरत है कि कालाबाजारी करने वाले ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं। इस पर सरकार को भी नजर रखनी चाहिए। अगर सभी लोग अफवाहों से दूर रहें, जरूरत भर ही खरीदारी करें और सरकार के साथ सहयोग करें तो किसी भी कृत्रिम संकट को टाला जा सकता है।

मध्य पूर्व में युद्ध और भारत की ऊर्जा सुरक्षा

देवेन्द्र कुमार बुडाकोटी

पश्चिम एशिया में अमेरिका, इज़राइल और ईरान से जुड़े चल रहे संघर्ष के वैश्विक प्रभाव हैं। भारत में इसका असर पहले से ही दिखाई देने लगा है, जहाँ खाना पकाने वाली गैस की घबराहट में खरीदारी और कालाबाज़ारी की घटनाएँ सामने आई हैं, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि पर्याप्त भंडार होने के कारण फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है।

हालाँकि, इससे जो बड़ा मुद्दा उभरकर सामने आता है, वह है भारत की ऊर्जा सुरक्षा। इस संघर्ष ने नागरिकों को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं, आपूर्ति की कमजोरियों और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता के प्रति अधिक जागरूक किया है।

वर्षों से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने और वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश करने के प्रयास कर रहा है। इनमें सौर, पवन, ज्वारीय, परमाणु और जलविद्युत ऊर्जा शामिल हैं, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में। ये पहल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाती हैं।

हम अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर शीघ्र संक्रमण की आवश्यकता के प्रति लगातार जागरूक हो रहे हैं। इस संकट ने कुछ महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को भी उजागर किया है, जैसे होर्मुज़ जलडमरूमध्य का रणनीतिक महत्व, जहाँ से विश्व के लगभग पाँचवें हिस्से के तेल की आपूर्ति और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। इस महत्वपूर्ण मार्ग में किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दे सकता है, जिसका विशेष प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ेगा।

भारत में ऊर्जा सुरक्षा को अक्सर पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक में आत्मनिर्भरता की कमी के संदर्भ में समझा जाता है। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 82% आयात करता है, जिससे वह विश्व के सबसे बड़े आयातकों में से एक बन जाता है। इस खपत का बड़ा हिस्सा परिवहन क्षेत्र से आता है–दो-पहिया और यात्री वाहनों के लिए पेट्रोल, ट्रकों और बसों के लिए डीज़ल, विमानन ईंधन, तथा कृषि में उपयोग।

इस निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की पहल की है, जिसमें दो-पहिया वाहन, कारें, बसें और औद्योगिक उपकरण शामिल हैं। इस परिवर्तन का उद्देश्य कच्चे तेल की खपत और आयात निर्भरता को कम करना है।

भारत का ऊर्जा परिदृश्य एक रणनीतिक परिवर्तन से गुजर रहा है। 2025 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 217 गीगावाट से अधिक हो चुकी है, और वर्तमान में कुल स्थापित क्षमता का लगभग 49% हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों, जिसमें नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं, से आता है। राष्ट्रीय बायो-ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और रूफटॉप सोलर कार्यक्रम जैसी सरकारी पहलें इस परिवर्तन के केंद्र में हैं। इसके अतिरिक्त, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार कर रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध ने यह दिखाया कि आधुनिक युद्ध शायद ही कभी एकतरफा होते हैं। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों का व्यापक समर्थन मिला, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में 'शक्ति संतुलन' की अवधारणा को दर्शाता है। हालांकि, जैसा कि हेनरी किसिंजर ने कहा था, 'अमेरिका के न तो स्थायी मित्र होते हैं और न ही शत्रु, केवल हित होते हैं।' यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए भी रूसी तेल और गैस पर अपनी निर्भरता को ध्यान में रखा, जो भू-राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा के जटिल संबंध को दर्शाता है।

वर्तमान मध्य पूर्व संकट से पहले ही भारत ने रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली थी, अक्सर रुपये-आधारित व्यापार जैसे अनुकूल प्रबंधों के माध्यम से, जो उसके आर्थिक और ऊर्जा हितों के अनुरूप था। रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान कुछ देशों द्वारा आलोचना के बावजूद, भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी।

जेलों में मौतें, आत्महत्याएं, अव्यवस्थाएं -सलाखों के पीछे भी असुरक्षित जीवन?

सुप्रीम कोर्ट का नोटिस,राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्वतः संज्ञान- जेल व्यवस्था, मानवाधिकार और न्याय प्रणाली पर वैश्विक प्रश्नचिन्ह ज़ेलों में विचाराधीन कैदी-न्याय से पहले सजा?क्या हम वास्तव में न्याय कर रहे हैं या एक और अन्याय को जन्म दे रहे हैं? सजा का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास होना चाहिए।सलाखों के पीछे भी सेफ नहीं?यह प्रश्न हमें आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करता है वैश्विक स्तरपर आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में जेल का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि उसे सुधारना और पुनर्वास के लिए तैयार करना भी होता है। परंतु जब जेलें स्वयं ही भय,बीमारी और उपेक्षा का केंद्र बन जाएं,तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम वास्तव में न्याय कर रहे हैं या एक और अन्याय को जन्म दे रहे हैं? सलाखों के पीछे भी सेफ नहीं?, यह केवल एक भावनात्मक प्रश्न नहीं,बल्कि कठोर वास्तविकता का दर्पण है।अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार,कैदियों से उनका स्वतंत्रता का अधिकार तो छीना जा सकता है,लेकिन उनका जीवन, स्वास्थ्य और गरिमा का अधिकार नहीं।

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

इसके बावजूद भारत सहित दुनियाँ के कई देशों में जेलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नेल्सन मंडेला नियम (यू एन स्टैंडर्ड मिनिमम् रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ़ प्रिजनर्स) स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए।उन्हें पर्याप्त भोजन,स्वच्छ पानी,स्वास्थ्य सुविधाएं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर इन सिद्धांतों और वास्तविकता के बीच गहरी खाई दिखाई देती है। जेलें, जो सुधार गृह मानी जाती हैं,अक्सर प्रताड़ना, हिंसा और उपेक्षा के केंद्र बन जाती हैं। यह स्थिति केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित देशों में भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं।

साथियों बात अगर हम भारत में जेलों की भीड़:एक गंभीर संरचनात्मक संकट को समझने की करें तो,भारत की जेल व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है,क्षमता से अधिक भीड़। कई राज्यों में जेलों की ऑक्यूपेंसी दर 150 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली की जेलों में 200 प्रतिशत तक कैदी भरे हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 150 प्रतिशत से अधिक है। इस भीड़ का सबसे बड़ा कारण है विचाराधीन कैदियों की अत्यधिक संख्या। आंकड़ों के अनुसार, भारत के लगभग 73.5 प्रतिशत कैदी ऐसे हैं जिनका अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है और वे केवल ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति न्यायिक प्रणाली की धीमी गति और मामलों के लंबित रहने का सीधा परिणाम है।

साथियों बात अगर हम विचाराधीन कैदीः न्याय से पहले सजा? इसको समझने की करें तो,विचाराधीन कैदी वह होते हैं जिन्हें अभी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है, फिर भी वे वर्षों तक जेल में बंद रहते हैं। यह स्थिति निर्दोषता की धारणा (प्रेसम्प्शन ऑफ़ इनोसेंस) के सिद्धांत के विपरीत है। न्यायिक देरी के कारण कई कैदी अपने संभावित सजा से अधिक समय जेल में बिता देते हैं। यह न केवल उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है।जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के लगभग 30-40 प्रतिशत पद खाली हैं।दिल्ली जैसी जगहों पर प्रति 200 कैदियों पर केवल एक डॉक्टर उपलब्ध है।इसका परिणाम यह होता है कि गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज नहीं हो पाता। अस्वच्छता और भीड़भाड़ के कारण टीबी, एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसी संक्रामक बीमारियां तेजी से फैलती हैं। वर्ष 2024 के पहले नौ महीनों में भारत में न्यायिक हिरासत में 1,558 मौतें दर्ज की गई,यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं, बल्कि एक गंभीर मानवीय संकट का संकेत है।इन मौतों के पीछे मुख्य कारण हैं,बीमारियां, आत्महत्याएं और चिकित्सा सुविधाओं की बहुत हद तक कमी।

साथियों बात अगर हम छत्तीसगढ़ का मामलाः एक राज्य, कई सवाल इसको समझने की करें तो छत्तीसगढ़ की जेलों में पिछले चार वर्षों में 285 कैदियों की मौत का मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला है। इनमें से 90 मौतें केवल 2022 में हुई और 66 मौतें जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच दर्ज की गई। राज्य सरकार ने इन मौतों के पीछे आत्महत्या और गंभीर बीमारियों को कारण बताया है।इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने जेलों में भीड़भाड़, डॉक्टरों की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को संभावित कारण बताया है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं,तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

साथियों बात अगर हम न्यायपालिका की सक्रियताः सुधार की दिशा में कदम को समझने की करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों की स्थिति पर ताजा आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश 26 मई 2026 तक सबमिट करने को दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने जेलों कीक्षमता भीड़भाड़ और महिला कैदियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत विवरण मांगा है।यह कदम दर्शाता है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। विशेष रूप से महिला कैदियों और उनके साथ रहने वाले बच्चों की स्थिति पर ध्यान देना एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि यह वर्ग अक्सर नीति निर्माण में उपेक्षित रह जाता है।साथियों बात अगर हम मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याएंः अदृश्य संकट इसको समझने की करें तो जेलों में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा लेकिन अनदेखा मुद्दा है। भीड़भाड़, पारिवारिक दूरी, सामाजिक कलंक और अनिश्चित भविष्य कैदियों को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। यही कारण है कि जेलों में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।ग्लोबल प्रिजन ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में जेलों के भीतर आत्महत्या और हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है। यह केवल एक देश की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर जेल सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

साथियों बात अगर हम संचार और मानवीय संपर्कः एक नई पहल इसको समझने की करें तो, कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए संचार के साधनों को बढ़ाना आवश्यक है। इसी दिशा में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें कैदियों को अपने परिवारजनों से मुफ्त वीडियो और ऑडियो कॉल के माध्यम से संवाद करने की अनुमति देने की बात कही गई है।यह पहल कैदियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने और उनके सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में मदद कर सकती है। आधुनिक तकनीक का उपयोग जेल सुधार के लिए एक प्रभावी माध्यम बन सकता है।

साथियों बात अगर हम सुधार की दिशा में आवश्यक कदम को समझने की करें तो जेल सुधार के लिए बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना होगा ताकि विचाराधीन कैदियों की संख्या कम हो सके। इसके लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट, डिजिटल सुनवाई और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना होगा।दूसरा, जेलों की क्षमता बढ़ाने और नए सुधार गृहों का निर्माण करना आवश्यक है। तीसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना होगा,डॉक्टरों की भर्ती, नियमित स्वास्थ्य जांच और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना होगा।चौथा कैदियों के लिए कौशल विकास और शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने होंगे ताकि वे समाज में पुनः स्थापित हो सकें।पांचवां, जेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें स्वतंत्र निगरानी तंत्र की स्थापना महत्वपूर्ण होगी।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यः एक साझा चुनौती को समझने की करें तो जेलों की बदहाल स्थिति केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका,ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और फिलीपींस जैसे देशों में भी जेलों में भीड़भाड़, हिंसा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं मौजूद हैं।हालांकि, कुछ देशों ने सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, नॉर्वे की जेल व्यवस्था को दुनिया में सबसे मानवीय माना जाता है, जहां कैदियों को पुनर्वास और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह मॉडल अन्य देशों के लिए प्रेरणा बन सकता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि न्याय का असली अर्थ,जेलें किसी भी सभ्य समाज का दर्पण होती हैं। यदि जेलों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो यह पूरे समाज की विफलता का संकेत है। सजा का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास होना चाहिए। 'सलाखों के पीछे भी सेफ नहीं? यह प्रश्न हमें आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करता है। क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां न्याय केवल कागजों तक सीमित है, या हम वास्तव में एक मानवीय और न्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं?समय आ गया है कि जेल सुधार को प्राथमिकता दी जाए,क्योंकि न्याय केवल अदालतों में नहीं, बल्कि जेलों की दीवारों के भीतर भी सुनिश्चित होना चाहिए।

जलवायु परिवर्तनः भविष्य नहीं, वर्तमान का महाविनाशकारी संकट

ललित गर्ग

आज मानव सभ्यता जिस सबसे बड़े संकट के सामने खड़ी है, वह युद्ध, महामारी या आर्थिक मंदी नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन है। दुनिया आज जलवायु संकट के ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां हर नया आंकड़ा खतरे की घंटी बनकर सामने आ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ताजा रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि 2015-2025 का दशक अब तक का सबसे गर्म दौर रहा है। यह केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं, बल्कि पृथ्वी के बदलते स्वभाव का गंभीर संकेत है। रिपोर्ट बताती है कि ग्रीनहाउस गैसों का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है और पृथ्वी का एनर्जी इम्बैलेंस लगातार बढ़ रहा है। महासागर, जो जलवायु संतुलन के सबसे बड़े नियंत्रक माने जाते हैं, अब 90 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त गर्मी सोख रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि पृथ्वी का तापमान केवल हवा में ही नहीं, जल और भूमि के भीतर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन अब धीरे-धीरे आने वाली समस्या नहीं रही, बल्कि यह वर्तमान का संकट बन चुका है। दुनिया के अनेक हिस्सों में असामान्य गर्मी, बाढ़, सूखा, चक्रवात और जंगल की आग जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। प्रति का संतुलन बिगड़ रहा है और मौसम का मिजाज अनिश्चित होता जा रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ रही है तो कहीं महीनों तक बारिश नहीं हो रही। यह असंतुलन सीधे-सीधे मानव जीवन, कृषि, जल संसाधनों और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इस बदलते मौसम ने सबसे ज्यादा मनुष्य के स्वास्थ्य पर हमला किया है।

भारत के संदर्भ में यह संकट और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के अनेक शहरों में तापमान 48 से 50 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पहले 45 डिग्री को ही अत्यधिक गर्मी माना जाता था। अब असामान्य गर्मी ने फरवरी और मार्च जैसे महीनों को भी झुलसाना शुरू कर दिया है। हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ रही हैं। इसका असर केवल स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि बिजली, पानी, खेती, श्रम, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी ने केवल मानव जीवन ही नहीं, बल्कि वन्यजीव, पेड़-पौधे और सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को भी संकट में डाल दिया है। जलवायु परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा कारण मानव का विकास मॉडल है। कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, अनियोजित शहरीकरण, औद्योगीकरण और संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पृथ्वी को लगातार गर्म कर रहा है। आज वैश्विक तापमान लगभग एक लाख 25 हजार वर्षों के उच्चतम स्तर के आसपास पहुंच चुका है। यह स्थिति बताती है कि समस्या प्रकृति में नहीं, बल्कि मानव की जीवनशैली और विकास की दिशा में है।

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां इस संकट को और अधिक खतरनाक बना रही हैं। दुनिया के अनेक हिस्सों में युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। युद्ध केवल मानव जीवन और अर्थव्यवस्था को ही नष्ट नहीं करते, बल्कि पर्यावरण को भी गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक, रसायन, धातु, ईंधन और आग से वातावरण में भारी मात्रा में जहरीली गैसें फैलती हैं। तेल भंडारों में आग, रासायनिक संयंत्रों का नष्ट होना और सैन्य गतिविधियां वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कई गुना बढ़ा देती हैं। इस प्रकार युद्ध और जलवायु परिवर्तन मिलकर पृथ्वी को दोहरे संकट की ओर धकेल रहे हैं। भारत सहित दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत जिले किसी न किसी जलवायु जोखिम के दायरे में आ चुके हैं। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। दूसरी ओर समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। यदि समुद्र स्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले दशकों में तटीय आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो सकता है। यह केवल पर्यावरण संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट भी बन सकता है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में तेजी से कटौती नहीं की गई, तो तापमान के नए-नए रिकॉर्ड टूटते रहेंगे और पृथ्वी रहने योग्य स्थान कम होती जाएगी। जल संकट, खाद्य संकट, स्वास्थ्य संकट और प्रवासन जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। दुनिया के अनेक वैज्ञानिक अब चेतावनी दे रहे हैं कि यदि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित नहीं किया गया, तो पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ सकता है। लेकिन इस संकट में ही अवसर भी छिपा हुआ है। यह समय विकास मॉडल को बदलने का है। ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। शहरों को कंक्रीट के जंगल बनाने के बजाय हरित शहर बनाना होगा। जल प्रबंधन को जन आंदोलन बनाना होगा। वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और नदियों के संरक्षण पर गंभीरता से काम करना होगा। कृषि को जलवायु अनुकूल बनाना होगा, कम पानी वाली फसलों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। साथ ही जिला स्तर पर हीट एक्शन प्लान, जल संरक्षण योजना, वृक्षारोपण अभियान और स्थानीय पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम लागू करने होंगे। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई केवल सरकारें नहीं जीत सकतीं, इसके लिए समाज, उद्योग, वैज्ञानिक और आम नागरिक सभी को मिलकर काम करना होगा।

दुनिया की महाशक्तियों के लिए यह समय सबसे बड़ी परीक्षा का समय है। यदि वे केवल आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति की दौड़ में ही उलझी रहीं और पृथ्वी के भविष्य की चिंता नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। उन्हें यह समझना होगा कि पृथ्वी बचेगी तो अर्थव्यवस्था भी बचेगी, मानव सभ्यता भी बचेगी और विकास भी बचेगा। यदि पृथ्वी ही तपती और असंतुलित हो गई, तो सारी प्रगति बेकार हो जाएगी। आज आवश्यकता है कि दुनिया की महाशक्तियां कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कठोर और बाध्यकारी नीतियां बनाएं, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करें, वनों की कटाई रोकें और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दें। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि अनेक क्षेत्र रहने योग्य नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चुनौती नहीं, वर्तमान का संकट है। यदि आज निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को एक असंतुलित और तपती हुई पृथ्वी विरासत में मिलेगी। यह तपती हुई पृथ्वी मानव जीवन के लिए विनाश का कारण भी बन सकती है। लेकिन यदि दुनिया समय रहते चेत गई, तो यही संकट एक नए, संतुलित और टिकाऊ विकास मॉडल की शुरुआत भी बन सकता है। पृथ्वी को बचाना अब विकल्प नहीं, मानव अस्तित्व की अनिवार्यता बन चुका है।

संसद में पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा; दर्शन सिंह बोले कलम में सुरक्षित होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने संसद के शून्य काल के दौरान भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक सुदृढ़ीकरण तथा पत्रकारिता के नाम पर हो रहे दुरुपयोग, दोनों पहलुओं पर संतुलित और ठोस नीति की आवश्यकता पर जोर दिया। सांसद चौधरी ने कहा कि पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है जो शासन और जनता के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करती है यह वहीं शक्ति है जो सत्ता को जवाबदेह बनाती है और समाज को जागरूक करती है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संस्थागत सुरक्षा और सुविधाएँ प्राप्त हैं वहीं पत्रकारों को अपेक्षित संरक्षण नहीं मिल पा रहा है पत्रकार विशेषकर फील्ड में कार्यरत अनेक जोखिमों और असुरक्षाओं का सामना कर रहे हैं इसी संदर्भ में उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या पत्रकारों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए एक व्यापक 'पत्रकार सुरक्षा एवं कल्याण नीति' बनाने पर विचार किया जा रहा है। सांसद चौधरी ने अपने वक्तव्य में प्रभावी शब्दों में कहा 'जब कलम सुरक्षित होगी, तब ही सच निर्भीक होकर सामने आएगा; और जब सच सामने आएगा तभी लोकतंत्र और मजबूत होगा' इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता की आड़ में हो रही ब्लैकमेलिंग और अनैतिक गतिविधियों पर भी चिंता जताई उन्होंने सरकार से कहा कि राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर एक पारदर्शी, जवाबदेह और सख्त तंत्र विकसित किया जाए जिससे पत्रकारिता की गरिमा बनी रहे।

डाकघरों से विदेश पार्सल भेजना हुआ आसान, ट्रैकिंग और फ्री पिक-अप सुविधा

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। संभाग के डाकघरों के माध्यम से अब नागरिक और व्यापारी विदेश में पार्सल भेज सकेंगे। डाक विभाग ने बड़े पार्सल के लिए नि:शुल्क पिक-अप और ट्रैकिंग की सुविधा भी देने का निर्णय लिया है। डाक विभाग की यह अंतर्राष्ट्रीय पार्सल सेवा एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है इससे अब स्थानीय स्तर पर ही विदेशों में पार्सल और दस्तावेज भेजना संभव हो सकेगा जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। यह सुविधा संभाग के सभी प्रमुख और उप डाकघरों में लागू की गई है जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे इस पहल से लोगों को महंगी निजी कूरियर सेवाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे किफायती दरों पर अपने पार्सल विदेश भेज पाएंगे। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पार्सल बुकिंग के समय ग्राहकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे ताकि सामग्री सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंच सके इसके अतिरिक्त हर पार्सल के लिए ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध होगी जिससे ग्राहक ऑनलाइन अपने पार्सल की स्थिति जान सकेंगे। बड़े और भारी पार्सल के लिए नि:शुल्क पिक-अप सुविधा इस सेवा की एक प्रमुख विशेषता है जिससे ग्राहकों को घर बैठे सुविधा मिलेगी इस पहल से छात्रों, व्यापारियों और विदेश में रहने वाले परिजनों को पार्सल भेजने वाले परिवारों को विशेष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है।

51 किलोग्राम के स्फटिक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा सकारात्मक ऊर्जा के लिए विशेष प्रभावशाली

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। बिलासपुर के नूतन चौक सरकंडा में साईं मंदिर परिसर में 51 किलोग्राम के स्फटिक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी मंदिर समिति का दावा है कि यह छत्तीसगढ़ का पहला स्फटिक शिवलिंग होगा तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 29 मार्च से शुरू होगा। मंदिर समिति के अमित तिवारी ने बताया कि हिमालय से प्राप्त शुद्ध स्फटिक (क्वार्ट्ज) से निर्मित यह शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है इसे अत्यंत शक्तिशाली, सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र और ध्यान-साधना के लिए विशेष प्रभावशाली माना जाता है तिवारी के अनुसार, शास्त्रों में स्फटिक शिवलिंग की पूजा के कई दिव्य लाभ बताए गए हैं। इनमें धन समृद्धि, कर्जमुक्ति, शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, शनि और राहु जैसे ग्रह दोषों से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और मन की शांति शामिल हैं सच्चे मन से पूजा करने पर मनोकामना पूर्ति का भी दावा किया गया है। महोत्सव के पहले दिन, 29 मार्च को शाम 4 बजे हरदेवलाल मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। यह यात्रा गोल बाजार, सदर बाजार, देवकीनंदन चौक, रामसेतु चौक, सीपत चौक होते हुए नूतन चौक स्थित स्फटिकेश्वर धाम पहुंचेगी। इस यात्रा में स्थापित होने वाले स्फटिक शिवलिंग और बनारस से आए नागा साधुओं का दल विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा।

जंगल में हिरण का शिकार, रिसार्ट में बनाया मीट, पर्यटन मंडल के रिसार्ट में पका मांस मैनेजर समेत 4 कर्मचारी गिरफ्तार

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पर्यटन मंडल के रिसार्ट में हिरण का शिकार किया गया वन विभाग की टीम ने रिसार्ट में छापेमारी कर हिरण के पके मीट बरामद किए है मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है मामला कोटा क्षेत्र के बेलगहना स्थित कुरदर के एथनिक रिसार्ट का है। दरअसल, वन विभाग को सूचना मिली थी कि बेलगहना वन परिक्षेत्र के कुरदर स्थित प्राइवेट रिसार्ट में हिरण का शिकार कर उसके मांस को पकाया जा रहा है अफसरों ने रिसार्ट में दबिश देकर तलाशी ली, तो किचन में कड़ाही पर मांस पकाया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने रिसार्ट में छापेमारी कर हिरण के पके मीट बरामद किए। जांच में पता चला कि एथनिक रिसार्ट पर्यटन मंडल संचालित करता है। जहां 8 से 10 कर्मचारी कार्यरत हैं। मैनेजर और कर्मचारियों के लिए हिरण का मीट बनाया जा रहा था टीम ने कुक रामकुमार टोप्पो समेत रिसॉर्ट के मैनेजर रजनीश सिंह सहित रमेश यादव, संजय वर्मा को पकड़ा है उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। वन विभाग के अफसरों ने मैनेजर रजनीश सिंह के साथ कर्मचारियों से पूछताछ की तब उन्होंने खुद का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता मांस किसका है। उन्होंने पूरा दोष कुक रामकुमार टोप्पो पर मढ़ दिया। जबकि कुक रामकुमार ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उसे गांव के जनक बैगा ने पत्ते में मांस लाकर दिया था। वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार आरोपियों का बयान दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अफसरों ने बताया कि जब्त मांस को जांच के लिए जबलपुर लैब भेजा जाएगा ताकि पुष्टि हो सके कि यह हिरण का ही मांस है या नहीं। हालांकि वन विभाग की जांच में हिरण के बाकी अवशेषों का कुछ पता नहीं चल सका है। कोटा-बेलगहना क्षेत्र में इससे पहले भी वन्य जीवों के शिकार हो चुके हैं। जंगल में करंट लगाकर बाघ-तेंदुआ के साथ ही जंगली सुअरों का भी शिकार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कई प्राइवेट रिसार्ट भी हैं जहां इसी तरह हिरण का शिकार कर मीट बनाया जाता है लेकिन वन विभाग के अफसरों ने अब तक प्राइवेट रिसार्ट में छापेमारी नहीं की है।

तारबाहर अंडरब्रिज 1 अप्रैल से 15 मई तक रहेगा बंद, मेंटनेंस के चलते डेढ़ महीने यातायात प्रभावित

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। तारबाहर स्थित रेलवे अंडरब्रिज 1 अप्रैल से 15 मई तक बंद रहेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने जर्जर हो चुके इस अंडरब्रिज की मरम्मत के लिए यह निर्णय लिया है लगभग डेढ़ महीने तक चलने वाले इस कार्य के दौरान यातायात प्रभावित रहेगा यह अंडरब्रिज (रुा.स.-366) बिलासपुर स्टेशन यार्ड के किमी 719/28-30 पर स्थित है। रेलवे प्रशासन के अनुसार बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अवधि में मरम्मत कार्य कराया जाएगा यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। लोग चुचुहियापारा रोड अंडरब्रिज और हेमुनगर रोड ओवरब्रिज का उपयोग कर आवागमन कर सकेंगे। रेल प्रशासन ने इस मरम्मत कार्य के कारण आमजन को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है और सहयोग की अपील की है।

राशन दुकान पर महिलाओं का हंगामा, वार्ड 32 की हितग्राहियों ने लगाया आरोप- राशन नहीं दिया

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। वार्ड क्रमांक 34 स्थित शासकीय राशन दुकान पर शनिवार को महिलाओं ने हंगामा कर दिया वार्ड 32 की महिलाओं ने सेल्समैन पर राशन न देने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए। विभाग ने निर्देश दिए थे कि मार्च माह का दो महीने का राशन वार्ड 32 के हितग्राहियों को वार्ड 34 की दुकान से दिया जाएगा। वार्ड 32 निवासी उमा कोली ने बताया कि 12 मार्च को उनकी बेटी ने राशन कार्ड जमा कर मशीन पर अंगूठा भी लगाया था लेकिन अब तक राशन नहीं मिला उन्हें लगातार दुकान के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। कमलेश शाक्य ने आरोप लगाया कि उनका राशन कार्ड 12 मार्च से जमा है फिर भी राशन नहीं दिया जा रहा। शनिवार को दुकान पहुंचने पर सेल्समैन ने कार्ड फेंक दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया उनका कहना है कि वार्ड 34 के लोगों को राशन दिया जा रहा है जबकि वार्ड 32 के हितग्राहियों को टालमटोल किया जा रहा है। कमलेश शाक्य ने फिजिकल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है महिलाओं ने वार्ड 32 के पार्षद कमल किशन शाक्य से भी शिकायत की पार्षद ने विभागीय अधिकारियों से बात कर वार्ड 32 की दुकान से ही राशन वितरण शुरू करने की मांग की है उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर कलेक्ट्रेट में धरना दिया जाएगा वार्ड 34 की दुकान के सेल्समैन सुनील राठौर ने आरोपों को गलत बताया उनका कहना है कि महिलाओं को सोमवार को राशन देने के लिए कहा गया था लेकिन वे उसी दिन विवाद करने लगीं जिला खाद्य अधिकारी तुलेश्वर कुर्रे ने बताया कि वार्ड 32 की दुकान को समिति से हटा दिया गया है और वार्ड 34 की समिति को वितरण की जिम्मेदारी दी गई है फिलहाल दुकान पर राशन सामग्री नहीं पहुंची है जैसे ही राशन पहुंचेगा सभी हितग्राहियों को वितरण कर दिया जाएगा।

शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच, यात्रियों को मिलेंगी अधिक कंफर्म बर्थ

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को अधिक कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए शालीमार-एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है यह सुविधा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली गाड़ी संख्या 18030/18029 में मिलेगी इस निर्णय के तहत गाड़ी में एक अतिरिक्त एसी-3 और एक स्लीपर कोच अस्थायी रूप से जोड़ा जाएगा। जानकारी के अनुसार, यह सुविधा 28, 29, 30, 31 मार्च और 01, 02, 03 अप्रैल को शालीमार से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस में उपलब्ध रहेगी। इसी तरह 30, 31 मार्च और 01, 02, 03, 04, 05 अप्रैल को एलटीटी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18029 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में भी यह सुविधा मिलेगी। इस अस्थायी सुविधा से इस मार्ग पर यात्रा करने वाले अधिक से अधिक यात्रियों को लाभ मिलेगा और उन्हें कंफर्म बर्थ प्राप्त हो सकेगी।

पूर्व डिप्टी सीएम के बेटे-बहू-पोती की हत्या, 2 को उम्रकैद;तीन बरी, हाईकोर्ट का फैसला

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम के बेटे-बहू और पोती की हत्या के 2 आरोपियों को उम्रकैद हुई है। 5 साल बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है इस मामले में 5 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 3 को बाइज्जत बरी कर दिया है। साल 2021 में उनके घर घुस कर परिवार के 3 सदस्यों की धारदार हथियार से हत्या की गई थी आरोप था कि जमीन विवाद और पैसों के लेन-देन को लेकर परिवार के ही बड़े बेटे, बहू, साले और उसके साथी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। जांच के बाद आरोपियों में बेटा बहू को संदेह का लाभ मिला, साले और दोस्त को सजा हुई है। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के भैंसमा गांव में प्यारे लाल कंवर का परिवार रहता था उनके 2 बेटों में पैसों और जमीन के लेनदेन को लेकर विवाद था। 21 अप्रैल 2021 को छोटे बेटे, उनकी बहू और 4 साल की पोती की हत्या हुई थी हत्यारों ने तीनों के चेहरे, सिर, गर्दन, मुंह, नाक, कान, पैर पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया था। जांच में सामने आया था कि बड़े भाई हरभजन के साले और उसके साथी ने घर घुसकर धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया था पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदेश्वर की अदालत में सरकारी अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी ने सभी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने एक महिला और चार पुरुष सहित कुल पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी जिसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी। अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दो आरोपियों की सजा को सही ठहराते हुए उम्रकैद बरकरार रखी, जबकि तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। एडवोकेट राजीव कुमार दूबे ने जानकारी दी कि आरोपियों में हरभजन सिंह कुंवर, उनकी पत्नी धनकुवंर, साला परमेश्वर, दोस्त राम प्रसाद मान्येवर, सुरेंद कुमार कंवर कुल 5 लोग आरोपी बनाए गए थे परमेश्वर और रामप्रसाद मन्नेवार को उम्रकैद हुई है अन्य 3 लोग बरी कर दिए गए हैं। अविभाजित मध्यप्रदेश में आदिवासी नेतृत्व का प्रमुख चेहरा स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर थे। कांग्रेस नेता प्यारेलाल कंवर कोरबा जिले की रामपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे।

पेट्रोल-डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं; मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के संभागायुक्तों, आईजी, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की बैठक में सभी जिलों में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और निगरानी तंत्र की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है इसलिए आम जनता को घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर अफवाहों के कारण अनावश्यक रूप से ईंधन और गैस का भंडारण किया जा रहा है जिससे आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है नागरिकों से अपील की गई कि वे केवल आवश्यकता अनुसार ही सामग्री का उपयोग करें। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखें और किसी भी प्रकार की कृत्रिम कमी न होने दें। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने बताया कि जिले में पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के स्टॉक की नियमित निगरानी की जा रही है अवैध भंडारण रोकने के लिए लगातार जांच और छापेमारी की कार्रवाई जारी है अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। किसी भी समस्या या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-3663, 1967 और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम 0771-2511975 पर संपर्क किया जा सकता है। कोरिया जिले के कंट्रोल कक्ष के मोबाइल नंबर 7648093823 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। एलपीजी उपभोक्ताओं को निर्धारित अंतराल पर ही सिलेंडर रिफिल बुकिंग कराने की सलाह दी गई है।

राजस्थान मिष्ठान में लगी आग, फर्नीचर जला, मिठाइयां हुईं खराब

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। इंद्रा चौक की राजस्थान मिष्ठान भंडार में रात 1 बजे बजे आग लग गई आग इतनी विकराल हुई कि ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी घटना से अफरा-तफरी मच गई बाजार क्षेत्र के अन्य दुकानदार समेत रहवासियों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने से एएसआई संजय रघुवंशी और फायर ब्रिगेड गाड़ी भी पहुंची। बिजली लाइनमैन बुलाकर सप्लाई कट कराई जिसके बाद आग बुझाने का कार्य शुरू किया करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। वरना आसपास की कपड़े दुकानों में आग फैल सकती थी जानकारी के मुताबिक राजस्थान मिष्ठान भंडार के आसपास रेडिमेट कपड़े की कई दुकानें है रात 1बजे राजस्थान मिष्ठान में आग लगी एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है आग से सारा फर्नीचर अन्य सामान जल गया मिठाई और नमकीन खराब हो गए।

नरवाई प्रबंधन का अनुकरणीय उदाहरणः ग्यारसपुर के किसान ने स्ट्रॉ रीपर से बनाया भूसा

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में फसल अवशेष (नरवाई) प्रबंधन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के बीच ग्यारसपुर विकासखंड के ग्राम मुडरा गणेशपुर के किसान श्री बलवीर सिंह दांगी ने एक सराहनीय पहल प्रस्तुत की है। उन्होंने हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद खेत में बची नरवाई को जलाने के बजाय स्ट्रॉ रीपर मशीन के माध्यम से उसका उपयोग कर भूसा तैयार किया। कृषक द्वारा अपनाई गई यह पद्धति न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो रही है। नरवाई जलाने से जहां एक ओर वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं इस प्रकार के वैज्ञानिक प्रबंधन से इन समस्याओं से बचाव संभव है। कृषि विभाग द्वारा लगातार किसानों को नरवाई न जलाने एवं वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में स्ट्रॉ रीपर, हैप्पी सीडर जैसी मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे खेत की उर्वरता बनी रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। श्री बलवीर सिंह दांगी की इस पहल को क्षेत्र में अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक बताया जा रहा है। स्थानीय कृषि अधिकारियों ने भी किसानों से अपील की है कि वे नरवाई जलाने के बजाय ऐसे आधुनिक एवं उपयोगी तरीकों को अपनाएं, जिससे आर्थिक लाभ के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।

नरवाई को जलाना पूर्णत प्रतिबंधित कियानरवाई प्रबंधन, उन्नत यंत्रों का उपयोग एवं धरती माता को सुरक्षित रखें

मीडिया ऑडीटर, धार (निप्र)। रबी सीजन में नरवाई जलाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रियंक मिश्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश अनुसार जिला अंतर्गत फसल कटाई के पश्चात बचाने वाले अवशेष कुंट एवं डंठल (नरवाई) को जलाना पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है। जिले मे इस सीजन मे अभी तक सेटेलाईट के माध्यम से जिन क्षेत्रो मे नरवाई जलाने की घटनाएं दर्ज की गई उन क्षेत्रो मे पंचनामा तैयार किया जाकर नोटिस जारी करने एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी। नरवाई में आग लगाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये नरवाई प्रबंधन के यंत्रों जैसे एक्स्ट्रा रीपर, रीपर, रीपर कंबाइंडर, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, मल्चर, बेलर इत्यादि का उपयोग किया जाना चाहिए। रीपर (ट्रैक्टर चालित/स्वचालित) खड़ी फसल को जड़ के पास से काटकर कतारों में व्यवस्थित रखता है। स्ट्रा रीपर यह यंत्र कंबाइन हार्वेस्टर के बाद खेत में बची नरवाई को काटकर भूसा तैयार करता है। इसके अतिरिक्त कृषक बन्धु फसल अवशेष को तेज धूप के बाद रोटावेटर का उपयोग करके अथवा देशी पाटा चलाकर गेहूं के बचे हुए स्ट्रा को जमीन में मिला सकते हैं। स्ट्रा को जमीन में मिलाने से जमीन की भौतिक दशा एवं कंपोस्टिंग खाद मिलने से जमीन की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। इसी कडी मे जिले के ग्राम तिसगांव, बडौदा, चालनी, सलकनपुर, चन्दवाडा इत्यादि गाव के कृषक श्री राहुल राठौर, घनश्याम पिता भेरूलाल, राजू पिता हीरालाल, कृष्णा पटेल इत्यादि कृषको द्वारा धरती मां को जलने से बचाने की दिशा में नरवाई प्रबंधन के यंत्रो का उचित उपयोग किया जा रहा है। इसलिए नरवाई नहीं जलाने हेतु कृषक बंधुओ से अपील की जाती है कि वर्तमान में हम धरती मां को सुरक्षित रखने से, मिटटी मे कार्बनिक तत्व की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से तथा जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान बचाने के उद्देश्य से मिट्टी स्वस्थ बनाए रखने हेतु नरवाई नहीं जलाएं उपरोक्त उचित प्रबंधन में यंत्रों का उपयोग करते हुए धरती मां को सुरक्षित रखें। जिले के कृषको द्वारा गेहूं की कटाई का कार्य अंतिम स्थिति है।

मेगा लीगल आउटरीच और जागरूकता शिविर का आयोजन किया

मीडिया ऑडीटर, धार (निप्र)। जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार श्री सिमोन सुलिया ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय-धार (म.प्र.) के द्वारा मेगा लीगल आउटरीच और जागरूकता शिविर का आयोजन आदर्श नर्सिंग कॉलेज-जैतपुरा धार में शुक्रवार को किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों, मुफ्त कानूनी सेवाओं की उपलब्धता और विभिन्न नालसा की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के बारे में जागरूक करना है। इन योजनाओं में असंगठित श्रमिकों, महिलाओं और बच्चों, मानव तस्करी के पीड़ितों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। मध्यस्थता, मध्यस्थता 2.0 अभियान और सामुदायिक मध्यस्थता को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इस मेगा लीगल आउटरीच और जागरूकता शिविर में शासन के विभिन्न विभाग जैसे-महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पुलिस विभाग आदि सम्मिलित होंगे एवं विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा ताकि लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सके।

गैस सिलेंडर एवं पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड नंबर से फोन कर गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग कराएं

मीडिया ऑडीटर, खण्डवा (निप्र)। खंडवा जिले में घरेलू गैस सिलेंडर एवं डीजल पेट्रोल की आपूर्ति नियमित हो रही है तथा किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री दिनेश सावले ने बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर एवं पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा गैस सिलेंडर एवं डीजल-पेट्रोल की वितरण व्यवस्था का सतत निरीक्षण किया जा रहा है।

मेगा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, वृद्धजनों को अधिकारों की दी गई जानकारी स्वास्थ्य परीक्षण कर रोगोपचार दवाइयां वितरित

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष शेख सलीम के मार्गदर्शन में आज शुक्रवार को हरि वृद्धाश्रम में मेगा विधिक जागरूकता शिविर एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस शिविर का आयोजन स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, पुलिस विभाग एवं नगरपालिका विदिशा के संयुक्त सहयोग से किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेख सलीम, विशेष न्यायाधीश जी.सी. शर्मा, जिला न्यायाधीश मनोज शर्मा, जिला न्यायाधीश कंचन सक्सेना, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितेन्द्र सिंह तोमर, न्यायिक मजिस्ट्रेट साकेत जैन सहित हरि वृद्धाश्रम के संचालक वेदप्रकाश शर्मा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशशेख सलीम ने कहा कि ÷मानव धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। माता-पिता भगवान के समान होते हैं, इसलिए वृद्धावस्था में उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने के बजाय उनकी सेवा करना प्रत्येक संतान का कर्तव्य है।÷ उन्होंने उपस्थित वृद्धजनों को उनके विधिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की।

विशेष न्यायाधीश जी.सी. शर्मा द्वारा वृद्धजनों को शॉल, श्रीफल एवं स्वच्छता किट वितरित की गई, जिससे उन्हें सम्मान और सहयोग का संदेश मिला।

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां उपस्थित लोगों को विधिक सहायता, सामाजिक योजनाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।

कार्यक्रम के अंत में हरि वृद्धाश्रम के संचालक वेदप्रकाश शर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा द्वारा समय-समय पर वृद्धाश्रम को सहयोग प्रदान किया जाता रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है।

यह शिविर न केवल विधिक जागरूकता बढ़ाने में सहायक रहा, बल्कि समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का संदेश भी देने में सफल रहा।

भूकंप आपदा से निपटने का प्रशिक्षण युवाओं को सिखाए गए बचाव और राहत के गुर

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने एवं भूकंप जैसी आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से एक दिवसीय ÷भूकंप पूर्व तैयारी, क्षमतावर्धन एवं बचाव संबंधी जन-जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम÷ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं एसडीईआरएफ के संयुक्त तत्वावधान में सम्राट अशोक पॉलिटेक्निक कॉलेज, विदिशा के स्मार्ट क्लास कक्ष में आयोजित हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर ने मां सरस्वती की प्रतिमा को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपर कलेक्टर डामोर ने प्रशिक्षण में शामिल एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र एवं स्काउट-गाइड के छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से युवाओं में आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया एवं राहत कार्यों में सहयोग की क्षमता विकसित होती है। उन्होंने प्रतिभागियों से अपील की कि वे प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को समाज में भी साझा करें।

कार्यक्रम के प्रारंभ में होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ की प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे ने प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्होंने एवं एसडीईआरएफ के प्रशिक्षित जवानों ने भूकंप एवं अन्य आपदाओं की प्रकृति, आपदा पूर्व तैयारी, सुरक्षित व्यवहार तथा ध्वस्त संरचनाओं में खोज एवं बचाव (ष्टस्स्क्र) तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ मयंक कुमार जैन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधानों, राहवीर योजना एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों को आपदा के समय कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं से अवगत कराया।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। यह प्रमाण-पत्र डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट मयंक कुमार जैन एवं प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे द्वारा प्रदान किए गए। इस अवसर पर एएसआई एल.एन. विश्वकर्मा सहित होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ के अधिकारी-कर्मचारी एवं जवान उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने वाले 10 अधिकारियों पर लगा 500-500 रुपए का अर्थदंड

मीडिया ऑडीटर, खण्डवा (निप्र)। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले एल-1 स्तर के कुल 10 अधिकारियो पर 500- 500 रुपए अर्थदंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें दर्ज होने के बाद ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया गया जिन्होंने कि शिकायतों को ÷अटेंड÷ ही नहीं किया था। इसलिए शिकायत ÷नॉट अटैंड÷ प्रदर्शित हो रही थी। उन्होंने बताया कि इन सभी अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस का जवाब संतोषप्रद प्राप्त न होने पर इन सभी 10 अधिकारियों पर 500-500 अर्थदंड लगाया गया है तथा राशि जमा भी करवा ली गई है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्राप्त शिकायतों को तुरंत अटेंड करें और शिकायत के संबंध में समय सीमा में पोर्टल पर अपना जवाब लिखित में दर्ज करा दें। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि एल-1 स्तर के जिन अधिकारियों से 500-500 रुपए अर्थदंड वसूला गया है, उनमें खण्डवा ब्लॉक के कृषि अधिकारी श्री दिनेश सोलंकी, मंडी सचिव पंधाना श्री हरेसिंह सोलंकी, हरसूद ब्लॉक के कृषि अधिकारी श्री कृष्णलाल कनासे छैगांवमाखन ब्लॉक के कृषि अधिकारी श्री मंगलेश पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पुनासा श्री अभिषेक त्रिवेदी, बाल विकास परियोजना अधिकारी पंधाना श्री रुपसिंह सिसोदिया, तहसीलदार मांधाता नरेन्द्र मुवेल, नायब तहसीलदार मोहना गजानंद चौहान, अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक गणेश तईकर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीराम भुसारिया शामिल हैं।

सफलता की कहानी - संकल्प से समाधान अभियान में सीहोर जिले ने प्राप्त की उल्लेखनीय उपलब्धियां

1,12,950 में से 1,11,346 प्रकरणों का किया गया निराकरण

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। सरकार गरीब, किसान, युवा, महिलाओं सहित सभी के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए सतत कार्य कर रही है। शासन द्वारा नागरिकों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च तक संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। जिले में अभियान की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ - 98.96 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण

संकल्प से समाधान अभियान: में सीहोर जिले में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। अभियान के तहत 25 मार्च तक जिले में कुल 52 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 46 कलस्टर, 05 ब्लॉक और एक जिला स्तरीय शिविर शामिल है।

इन शिविरों में शासन की 106 सेवाओं और योजनाओं से नागरिकों को लाभान्वित किया गया। अभियान के तहत जिले में अभी तक 1,12,950 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1,11,346 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जो 98.96 प्रतिशत की उल्लेखनीय उपलब्धि को दर्शाता है। शेष रहे आवेदनो को भी शीघ्र ही निराकृत कर दिया जाएगा। राज्य में प्रति जिला औसत 81 हज़ार आवेदन के सापेक्ष सीहोर जिले में 37 प्रतिशत अधिक आवेदन एकत्रित किये गये है। इसी प्रकार प्रति जिला औसत निराकरण 80 हज़ार आवेदन के सापेक्ष जिला सीहोर में 38 प्रतिशत अधिक आवेदन निराकृत किये गये है। अभियान के अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों की 542 ग्राम पंचायतों एवं 158 नगरीय वार्डो को शामिल करते हुए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है।

प्रमुख विभागीय उपलब्धियां: अभियान के तहत जिले के विभिन्न विभागों द्वारा उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। सहकारिता विभाग द्वारा 25,584 किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 15,545 भवन निर्माण अनुज्ञा एवं राजस्व विभाग द्वारा 11,878 खसरा/खतौनी प्रतिलिपियाँ प्रदान की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 9,774 आयुष्मान कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हजारों की संख्या में आय, निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

कलेक्टर और विधायक ने पुस्तक मेले का निरीक्षण किया

मीडिया ऑडीटर, खण्डवा (निप्र)। आगामी शिक्षा सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 12 वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खंडवा में 5 दिवसीय ÷पुस्तक मेला÷ आयोजित किया जा रहा है। यह पुस्तक मेला 26 से 30 मार्च तक जिमखाना ग्राउंड के पास, सूरजकुंड स्थित पी एम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित हो रहा है। शुक्रवार को कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता और विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे ने पुस्तक मेले में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान वहां मौजूद पुस्तक विक्रेताओं और विद्यार्थियों के पालकों से चर्चा कर पुस्तक मेले में किताबो, अभ्यास पुस्तिकाओ और अन्य स्टेशनरी सामग्री की उपलब्धता, तथा उन पर दी जाने वाली छूट के संबंध में जानकारी ली।

इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी एस सोलंकी सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने इस दौरान निर्देश दिए कि पुस्तक मेले में आने वाले विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को डिस्काउंट का लाभ देते हुए उचित मूल्य पर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि बुक स्टॉल पर कौन कौन से स्कूलों की पुस्तके उपलब्ध है, पुस्तक विक्रेता इस संबंध में अपने स्टॉल पर फ्लेक्स या ड्राइंग शीट पर लिखकर प्रदर्शित करें ।उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल व कक्षा की पुस्तको की सूची दुकान के काउन्टर पर उपलब्ध रहे। जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी एस सोलंकी ने इस अवसर पर बताया कि मेले में कुल 16 स्टेशनरी स्टोर्स द्वारा अपने स्टॉल लगाए हैं। अभी तक लगभग 260 पालकों और विद्यार्थियों ने मेले में आकर पुस्तक व स्टेशनरी सामग्री क्रय की। पालकों को स्टेशनरी सामग्री क्रय करने पर डिस्काउंट भी मिला है, जिस पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की।

बीज संघ हाइब्रिड बीजों का उत्पादन कर किसानों को बाजार से आधी कीमत पर उपलब्ध कराएगाः मंत्री

एम.पी. के चीता बीज' को विश्व स्तरीय ब्रांड बनाने की होगी पहलनई सीड प्रोसेसिंग यूनिट और किसानों के प्रशिक्षण पर दें विशेष ध्यान

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने राज्य सहकारी बीज एवं विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (बीज संघ) के संचालक मंडल की बैठक में बीज उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा किसानों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बीज संघ द्वारा मक्का, नॉन-जीएम कपास एवं सब्जियों के हाइब्रिड बीजों का उत्पादन एवं विपणन किया जाएगा। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज बाजार मूल्य की तुलना में लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि इससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मंत्री श्री सारंग ने बीज संघ के 'चीता बीज' को विश्व स्तरीय ब्रांड के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजों की गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा सोशल मीडिया, कृषि मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। बैठक में बताया गया कि बीज प्रसंस्करण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई सीड प्रोसेसिंग यूनिट एवं कलर सॉर्टेक्स मशीनें स्थापित की जाएंगी। प्रथम चरण में यह कार्य गुना एवं खरगोन में प्रारंभ किया जाएगा, जिसे पैक्स एवं सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के अन्य जिलों में विस्तारित किया जाएगा।

मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रशिक्षित किया जाए। जिन किसानों ने बीज उत्पादन में अच्छा कार्य किया है, उनके माध्यम से अन्य किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए तथा प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बीज उत्पादन योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि बीज संघ आगामी समय में बीज उत्पादन, ब्रांडिंग, प्रसंस्करण एवं विपणन को मजबूत करते हुए किसानों को किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ कार्य करे। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक वर्णवाल, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक संस्थाएं श्रीमती शीला दाहिमा, राज्य विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्री अभिजीत अग्रवाल, बीज निगम के प्रबंध संचालक श्री महेंद्र दीक्षित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

वर्ल्ड कप से पहले गुरजंत सिंह ने लिया संन्यास

दो बार ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय टीम का रहे हिस्सा

नई दिल्ली, एजेंसी। वर्ल्ड कप से पहले टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे फॉरवर्ड गुरजंत सिंह ने शुक्रवार (27 मार्च) को अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया। भारत के लिये 2017 में पदार्पण करने वाले 31 वर्ष के गुरजंत ने 130 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 33 गोल किये। पिछले साल जून में आखिरी बार भारत के लिये खेलने वाले गुरजंत ने दिल्ली में हॉकी इंडिया सालाना पुरस्कारों के दौरान अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। गुरजंत ने कहा, 'मैंने यहां मौजूद दिग्गजों को देखकर हॉकी खेलना शुरू किया था और उनके साथ भारत के लिये खेलने का मेरा सपना पूरा हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। मेरा यह सफर बहुत अच्छा रहा और टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद ऐतिहासिक पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहा। इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में भी उसे प्रदर्शन को दोहराया। मैं बहुत खुशी और गर्व के साथ विदा ले रहा हूं।'

गुरजंत के नाम भारतीय रिकॉर्डः गुरजंत के नाम सबसे तेज अंतरराष्ट्रीय गोल का भारतीय रिकॉर्ड भी है। उन्होंने एफआईएच प्रो लीग 2020 में नीदरलैंड के खिलाफ 13 सेकंड में गोल दागा था। उन्होंने यह भी कहा कि वह घरेलू हॉकी और लीग खेलते रहेंगे, लेकिन कोचिंग के बारे में अभी सोचा नहीं है। गुरजंत ने कहा, 'मैंने पिछले जून के बाद से अंतरराष्ट्रीय हॉकी नहीं खेली है। इस साल हॉकी इंडिया लीग खेली और आगे भी खेलूंगा, लेकिन कोचिंग को लेकर अभी सोचा नहीं है।'

अर्जुन पुरस्कार से नवाजे गए

गुरजंत के साथी खिलाड़ी रहे दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश संन्यास के बाद जूनियर टीम के कोच बने, जिसने पिछले साल चेन्नई में एफआईएच जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीता था। अमृतसर के खैलारा गांव में जन्मे गुरजंत लखनऊ में 2016 जूनियर विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे थे। उन्होंने फाइनल में गोल भी दागा था। इसके अलावा वह एशियाई खेल 2023 और 2017 एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। उन्हें 2021 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। हॉकी इंडिया ने उन्हें पुरस्कार समारोह के दौरान सम्मानित करके पांच लाख रुपये का पुरस्कार दिया।

WWE में 12 साल बाद लौटने को तैयार दिग्गज रेसलर

2002 में ट्रिपल एच ने दी थी मात; क्या WrestleMania में होगी वापसी?

नई दिल्ली, एजेंसी। 42 का आयोजन 18 व 19 अप्रैल को होगा। इससे पहले कई बड़े सरप्राइज की उम्मीद भी फैंस जताने लगे हैं। उसी बीच एक दिग्गज रेसलर ने 12 साल बाद कंपनी में वापसी की इच्छा बताई है। उन्होंने हर बात पर विचार करने को भी कहा है। WWE में 2000 से 2010 के दशक में एक नाम बहुत गूंजता था और वह था रॉब वैन डैम का। उन्हें शॉर्ट फॉर्म में आरवीडी (RVD) के नाम से भी जाना जाता था। आरवीडी की चपलता और उनके फास्ट मूव्स अक्सर चर्चा में रहते थे। केन और आरवीडी की जोड़ी भी काफी मशहूर हुई थी। फिर 2002 में WWE Unforgiven में ट्रिपल एच ने उन्हें मात भी दी थी। 2014 में वह कंपनी से चले गए थे लेकिन अब एक इंटरव्यू में इस रेसलर ने फिर से वापसी की हुंकार भरी है। वैसे तो आरवीडी और ट्रिपल एच की राइवलरी थी लेकिन अब जब ट्रिपल एच कंपनी के चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं तो उनके कार्यकाल में कंपनी फिर से काफी अच्छा कार्य कर रही है। इस दौरान जॉन सीना, एजे स्टाइल्स जैसे रेसलर्स की आइकॉनिक विदाई भी चर्चा का विषय रही। वहीं अब जब रेसलमेनिया 42 का आयोजन नजदीक है तो कई दिग्गजों की वापसी की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। उसी कड़ी में आरवीडी के ताजा इंटरव्यू ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है।

क्या बोले रॉब वैन डैम?

TMZ Inside The Ring पॉडकास्ट में बात करते हुए रॉब वैन डैम ने कंपनी में वापसी की इच्छी जाहिर की। उन्होंने साफतौर पर कहा कि वह किसी भी बात पर विचार करने के लिए तैयार हैं। वहीं आरवीडी ने यह भी कहा कि उनका नंबर कंपनी के ऑफिसर्स के पास है, वह उनसे किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि, मैं WWE वर्ल्ड में आ रहा हूं और वहां भी इस बारे में बात कर सकते हैं। रिटायरमेंट की किसी भी खबर को आरवीडी ने खारिज किया और इस बारे में बात तक करने से इनकार कर दिया।

दिल्ली कैपिटल्स की ताकत और कमजोरी

खिताब का सूखा खत्म करने पर नजर

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में दिल्ली कैपिटल्स खिताब का सूखा खत्म करने उतरेगी। फ्रेंचाइजी 2008 से ही लीग का हिस्सा है। वह दिल्ली डेयरडेविल्स से दिल्ली कैपिटल्स बन गई है, लेकिन वह अबतक खिताब नहीं जीत पाई है। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के 18 सीजन में केवल एक बार फाइनल खेल पाई है। 2020 में उसे मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा था।

आईपीएल के 19वें सीजन में अक्षर पटेल की अगुआई में दिल्ली कैपिटल्स उम्मीद करेगी कि वह इस साल 18 साल का सूखा खत्म करे। अक्षर पिछले सीजन भी टीम के कप्तान थे। शुरुआत में टीम ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन बाद में प्रदर्शन इतना गिरा कि टीम प्लेऑफ तक में नहीं पहुंच पाई। दिल्ली कैपिटल्स के टीम मैनेजमेंट को अनावश्यक प्रयोग से बचना होगा।

दिल्ली कैपिटल्स की ताकत- दिल्ली कैपिटल्स की ताकत की बात करें तो बेन डकेट ने आईपीएल के इस सीजन से नाम वापस ले लिया है, लेकिन इसके बाद भी टीम के पास पृथ्वी शॉ, केएल राहुल और पथुम निसांका जैसे ओपनिंग बल्लेबाज के विकल्प हैं। मध्यक्रम में ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी हैं।

लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव और आकिब नबी जैसे गेंदबाज हैं। ऑलराउंडर अक्षर पटेल और प्रिंस यादव जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम और संतुलित दिखाई देती है।

दिल्ली कैपिटल्स की कमजोरी

कमजोरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की उपलब्धता पर संशय है। स्टार्क जैसे गेंदबाज का न होना किसी भी टीम के लिए चिंता का विषय है। दिल्ली कैपिटल्स पिछले सीजन पहले 7 में केवल दो मैच हारी थी। इसके बाद भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। लगातार 4 मैच जीतने के बाद भी बदलाव के कारण संतुलित प्लेइंग 11 नहीं बन पाया। टीम मैनेजमेंट को इस गलती से बचना होगा।

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11

पथुम निसांका, केएल राहुल, नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार।

इम्पैक्ट प्लेयर - अभिषेक पोरेल/ टी नटराजन

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड

अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, करुण नायर, डेविड मिलर, पथुम निसांका, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, औकिब डार, नीतीश राणा, मिशेल स्टार्क, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, लुंगिसानी एनगिडी, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव।

ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टूर्नामेंट में विवाद

'फ्री इमरान खान' लिखी टी-शर्ट पहन मैच देखने पहुंचा दर्शक

नई दिल्ली, एजेंसी। 'फ्री इमरान खान' लिखी टीशर्ट पहनने के कारण मेलबर्न में एक क्रिकेट प्रशंसक को शेफील्ड शील्ड फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। हालांकि, बाद में अधिकारियों ने इसे राजनीतिक बयान के बजाय मानवीय मुद्दा मानते हुए अपना रुख बदल लिया।

'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' के अनुसार सुरक्षा कर्मचारियों ने विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच शेफील्ड शील्ड फाइनल के पहले दिन जंक्शन ओवल में प्रवेश करने से पहले ल्यूक ब्राउन नाम के प्रशंसक से अपनी टीशर्ट ढकने को कहा। सुरक्षा कर्मचारियों ने पहले तो इस संदेश को एक राजनीतिक बयान माना जो जेल में बंद पाकिस्तानी क्रिकेट दिग्गज के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन स्थिति की समीक्षा करने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता ने कहा कि अब इस मामले को मानवीय नजरिए से देखा जा रहा है।

ब्राउन हैरान

ब्राउन ने 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' से कहा, 'जब मुझे रोका गया तो मुझे काफी हैरानी हुई। मैं उनकी बात समझता हूं कि उन्हें कई परिस्थितियों से भी निपटना होता है। इसलिए अगर वे एक आम नियम लागू करते हैं तो उनके लिए चीजें आसान हो जाती हैं।'

इमरान खान 2023 से जेल में

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता ने इसी अखबार से कहा, 'क्रिकेट समुदाय में इमरान खान की भलाई को लेकर चिंता को देखते हुए हमारा मानना ??है कि यह एक मानवीय मुद्दा है और हम उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे।' यह घटना 14 पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिनों बाद हुई है, जिनमें सुनील गावस्कर, कपिल देव और ग्रेग चैपल जैसे दिग्गज शामिल हैं। इस याचिका में पाकिस्तानी सरकार से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को उचित चिकित्सा देखभाल और मानवीय व्यवहार प्रदान करने का आग्रह किया गया था। इमरान खान 2023 से जेल में हैं।

चिन्नस्वामी में 10 महीने बाद मैच

बेंगलुरु-सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबले की मौसम और पिच रिपोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (ढ्ढक्क 2026)का पहला मैच शनिवार (28 मार्च) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (ऋष्टक्च)और सनराइजर्स हैदराबाद (स्त्रञ्ज) के बीच खेला जाएगा। बेंगलुरु में शनिवार को मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में चौके-छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। इस मैदान पर खूब रन बनता है। हालांकि, बीते 10 महीने में यहां एक भी मैच नहीं हुआ है। आइए जानते है बेंगलुरु की मौसम और चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की जानकारी। आरसीबी-सनराइजर्स के बीच आईपीएल 2026 का पहला मैच सेंटर पिच पर खेला जाएगा। चिन्नस्वामी स्टेडियम काफी छोटा है और हाई-स्कोरिंग ग्राउंड है। आरसीबी-सनराइजर्स के पास ऐसी बल्लेबाजी यूनिट है, जो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। पिछले कुछ हफ्तों से बेंगलुरु में बहुत ज्यादा गर्मी और मैच के दौरान भी मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है।

पिच रिपोर्टः एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भले ही 10 महीने से मैच न हुआ हो, लेकिन यहां कि पिच में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां की पिच बल्लेबाजों के मुफीद होगी और हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद है। टॉस जीतने वाली टीम के पहले गेंदबाजी कर सकती है। यहां चेज करना काफी आसान होता है। टी20 क्रिकेट में अब कोई भी टारगेट सुरक्षित नहीं लगा, लेकिन 200 से 220 से तक के स्कोर भी अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है।

कैसा रहेगा मौसमः बेंगलुरु के मौसम के अनुमान के मुताबिक शनिवार को आसमान साफ ??रहेगा और सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से मौसम उमस वाला रहेगा। दिन का तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शाम को तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान नहीं है।

तैराक मणिकांत ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की, छत्तीसगढ़ की अनुष्का ने दूसरा पदक जीता

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कर्नाटक के तैराक मणिकांत एल ने 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की। महिला वर्ग में ओडिशा की अंजली मुंडा ने लगातार दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मेजबान छत्तीसगढ़ के लिए भी खुशखबरी रही, जब स्थानीय खिलाड़ी अनुष्का भगत ने महिला 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले रेस में रजत जीतकर पदक तालिका में इजाफा किया। मणिकांत ने पहले दिन 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक और 50 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण जीतने के बाद 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले रेस में 2~25.93 सेकंड का समय बनाकर दबदबा बनाए रखा। त्रिपुरा के रियाज त्रिपुरा 2~34.04 सेकंड के साथ दूसरे और ओडिशा के कान्हु सोरेन 2~36.21 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में अंजली ने 2~53.82 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। अनुष्का भगत (2~59.33) ने रजत और ओडिशा की अंजली मल्लिक (3~06.13) ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया।

कर्नाटक 12 पदक (आठ स्वर्ण और दो रजत और एक कांस्य) के साथ तालिका में शीर्ष पर है, जबकि ओडिशा 14 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। ओडिशा स्वर्ण पदक के मामले में कर्नाटक से पीछे है। राज्य के नाम पांच स्वर्ण, एक रजत और आठ कांस्य पदक है। भारोत्तोलन में असम की मणिखा सोनवाल और मिजोरम के इसाक मालसॉमट्लुंगा ने चोटों के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया। मणिखा ने महिला 48 किग्रा वर्ग में स्नैच में 57 किग्रा और क्लीन एंव जर्क में 75 किग्रा उठाकर कुल 132 किग्रा के साथ स्वर्ण पदक जीता। ओडिशा की दीपा रानी मल्लिक 120 किग्रा के साथ रजत और अंडमान एवं निकोबार की अलास्का अलीना 116 किग्रा के साथ कांस्य पर रहीं। मिजोरम के इसाक मालसॉमट्लुंगा ने स्नैच में 108 किग्रा और क्लीन एंव जर्क में 130 किग्रा भार उठाकर कुल 235 किग्रा के साथ स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया। बाबूलाल हेम्ब्रोम ने कुल 230 किग्रा भार उठाकर रजत पदक के साथ तालिका में झारखंड का खाता खोला। ओडिशा के सुभ्रत नाइक क्लीन एवं जर्क में 122 किग्रा उठा पाए और कुल 228 किग्रा के साथ कांस्य पदक हासिल करने में सफल रहे।

मुचोवा को हराकर गॉफ पहली बार मियामी ओपन के फाइनल में, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी होगा सामना

फ्लोरिडा दुनिया की नंबर 4 खिलाड़ी कोको गॉफ पहली बार मियामी ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। नंबर 13 सीड कैरोलिना मुचोवा को 6-1, 6-1 से हराकर मियामी की रहने वाली यह खिलाड़ी अपने छठे डब्ल्यूटीए 1000 फ़ाइनल में पहुंचने के बाद, अपने 12वें WTA खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। शुरुआत में एक ब्रेक गंवाने के बाद, गॉफ ने आखिरी 13 में से 12 गेम जीतकर एक घंटे 20 मिनट में जीत हासिल की; इस जीत की ख़ास बात यह थी कि उन्होंने मुचोवा की सर्विस को छह बार ब्रेक किया।

अब वह चेक खिलाड़ी के खिलाफ छह मैचों में अजेय हैं और 2026 में दो बार उन्हें हरा चुकी हैं। गॉफ ने सीजन की अपनी शुरुआत के बारे में प्रेस से कहा, इस साल मेरे कुछ मैच काफी मुश्किल रहे, लेकिन यह पिछले साल से बेहतर है। मुझे लगता है कि यह सब मेरे खेल को बेहतर बनाने और उसे और मजबूत करने की कोशिश का नतीजा है और मुझे लगता है कि सुधार हो रहे हैं खासकर मेरे फोरहैंड में, मैं इस बात से खुश थी कि पूरे टूर्नामेंट में मेरा खेल कैसा रहा। शनिवार के फाइनल में गॉफ का अगला मुकाबला दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका से होगा जिन्होंने गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबाकिना को 6-4, 6-3 से हराया था। गॉफ का सबालेंका से 12 बार मुकाबला हुआ है, हाल ही में 2025 में मैड्रिड फाइनल, रौलां गैरो फाइनल और ड्ड्ड्र फाइनल रियाद ग्रुप स्टेज में; जिसमें फ्रांस में हुए मुकाबले में अमेरिकी खिलाड़ी गॉफ ने जीत हासिल की थी। सबालेंका और गॉफ़ के बीच टूर-लेवल पर अब तक 12 मुकाबले हुए हैं, जिनमें दोनों ने 6-6 जीत हासिल की हैं।

मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बस्तर में आजीविका विकास हेतु कार्यशाला

मुख्य फ़ोकस नक्सल मुक्त क्षेत्रों में स्थायी एवं समावेशी विकास

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राज्य में नक्सलवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में तीव्र, स्थायी एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज मुख्य सचिव श्री विकास शील की अध्यक्षता में इन जिलों के आजीविका संवर्धन हेतु राज्यस्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव कृषि श्रीमती सहला निगार, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि वोरा, सचिव श्री भीम सिंह सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, गृह एवं जेल विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्रामोद्योग विभाग तथा ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनीश कुमार द्वारा इन क्षेत्रों के लिए तैयार समन्वित नीति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि जैसे-जैसे छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होता जा रहा है, हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। जिन क्षेत्रों में अब तक विकास नहीं पहुंच सका, वहां पहुंचकर हमें सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप सभी विभागों को समन्वित दृष्टिकोण के साथ आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना तैयार कर कार्य करना होगा। स्थानीय संसाधनों के आधार पर आजीविकामूलक गतिविधियों के संचालन एवं संवर्धन पर विशेष जोर दिया जाए।

कार्यशाला में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जिला स्तर के अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान क्लस्टर आधारित एवं ब्लॉक केंद्रित आजीविका मॉडल पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मॉडल के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वनोपज, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प एवं सूक्ष्म उद्यमों को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की योजना है। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन एवं बेहतर कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यशाला में जिला, विकासखंड एवं क्लस्टर स्तर पर त्रिस्तरीय योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार कर उन्हें तेजी से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय में वास्तविक वृद्धि सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया गया।

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि उत्पादन से लेकर विपणन तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगले चरण में प्रत्येक विकासखंड में संभावित आजीविका क्लस्टरों की पहचान कर 60 दिनों के भीतर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसमें सर्वेक्षण, योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा शामिल होगी। कार्यशाला में प्रस्तुत रणनीति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का मजबूत आधार बनेगी। यह पहल ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कार्यशाला में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में आजीविका परिवर्तन एवं जीवन स्तर में सुधार हेतु परिवारों की आय बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। एनसीएईआर (NCAER) के सर्वेक्षण के अनुसार इन क्षेत्रों के 85 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अगले ढाई से तीन वर्षों में इसे बढ़ाकर न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक ने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विविधीकरण, सामूहिकीकरण, प्रौद्योगिकी एवं संतृप्ति के चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित रणनीति पर प्रकाश डाला। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को कम से कम तीन आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाएगा तथा प्रत्येक जिले में चार प्रमुख आजीविका क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह पहल क्लस्टर आधारित एवं बाजार उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित होगी, जिसमें सशक्त मूल्य श्रृंखला तंत्र विकसित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को सक्रिय नेतृत्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नाबार्ड, एफईएस तथा प्रदान जैसे सहयोगी संगठनों द्वारा एनटीएफपी (लघु वनोपज) मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने एवं एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए गए।

हौसला, हुनर और योजनाओं के सहारे महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का छोटा सा गांव मनियारी आज एक बड़ी सीख दे रहा है- अगर इरादे मजबूत हों और सही मौके मिल जाएं, तो बदलाव दूर नहीं होता। यहां की पांच महिलाओं ने अपने साहस, आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव में नई सोच की शुरुआत कर दी। इस बदलाव की शुरुआत हुई अनुसूया साहू से। बचपन से सिलाई में माहिर अनुसूया के पास हुनर तो था, लेकिन आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के चलते वह आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उनका सपना कहीं दब सा गया था। मार्च 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को 1000 हजार रूपए की प्रत्येक माह आर्थिक मदद दिए जाने के उद्देश्य से शुरू की गई महतारी वंदन योजना ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई। हर महीने मिलने वाली इस सहायता राशि को खर्च करने के बजाय उन्होंने बचाने का फैसला किया। छह महीने की बचत के बाद उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और घर से ही काम शुरू किया। शुरुआत भले ही छोटी थी, कपड़ों की आल्टरिंग और साधारण सिलाई, लेकिन काम की गुणवत्ता ने जल्द ही उन्हें पहचान दिला दी। अनुसूया की कोशिशों ने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। ओमकारेश्वरी साहू ने उनसे सिलाई सीखी और अपना काम शुरू किया। इसके बाद पार्वती, गंगा और हेमिनी भी जुड़ती चली गईं। देखते ही देखते यह पहल एक मजबूत महिला समूह में बदल गई, जहां सहयोग और सीखने की भावना ने इसे आगे बढ़ाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जानकारी दी और पंजीकरण में मदद की। योजना के तहत मिली 5000 रुपये की सहायता राशि का उपयोग महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदने और अपने काम को विस्तार देने में किया। सही जानकारी और योजनाओं के उपयोग ने इनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी। आज ये पांचों महिलाएं मिलकर एक सफल सिलाई केंद्र चला रही हैं। वे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए कपड़े तैयार कर रही हैं। समय पर काम और बेहतर गुणवत्ता के कारण गांव के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी उनकी पहचान बन चुकी है। इस पहल से उनकी आय में वृद्धि हुई है। अब वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दे रही हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब वे परिवार के फैसलों में भी बराबरी से भागीदारी निभा रही हैं। इन महिलाओं की सफलता अब गांव की अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ वे समाज में नई पहचान बना रही हैं।

खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स :

केरल की एथलेटिक्स टीम पहुंची जगदलपुर पारंपरिक लोकनृत्य से हुआ भव्य स्वागत

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। आदिवासी खिलाड़ियों को समर्पित इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है, जो भारत की खेल यात्रा में आदिवासी सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तहत बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के धरमपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं का आयोजन 30 मार्च से 2 अप्रैल तक किया जाएगा। खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स के अंतर्गत बस्तर जिले में आयोजित होने वाली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए केरल राज्य की टीम आज जगदलपुर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा खिलाड़ियों का आत्मीय स्वागत किया गया।

बस्तर के हृदय स्थल जगदलपुर में आगामी 30 मार्च से 2अप्रैल तक आयोजित होने वाले चार दिवसीय नेशनल ट्राइबल गेम्स का उत्साह अब धरातल पर दिखने लगा है। इस राष्ट्रीय खेल महाकुंभ में अपनी चुनौती पेश करने के लिए देश के कोने-कोने से खिलाड़ियों का आगमन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में केरल राज्य से 17 सदस्यीय एक दल किरंदुल पैसेंजर के माध्यम से जगदलपुर रेलवे स्टेशन पहुँचा।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 : महिला हॉकी में एकतरफा मुकाबले

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंतर्गत राजधानी रायपुर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में आज तीसरे दिन महिला हॉकी प्रतियोगिता के मुकाबले खेले गए। पूल 'ए' में खेले गए मैच में मध्य प्रदेश ने बिहार को 9-0 से पराजित किया। वहीं, पूल 'बी' के मुकाबलों में झारखंड ने गुजरात को 16-0 से और ओडिशा ने तमिलनाडु को 14-0 से हराया। खेले गए सभी मैच एकतरफा रहे, जिनमें विजेता टीमों ने पूरे समय खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा।

गौरतलब है कि 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स' के इस प्रथम संस्करण में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 3,800 खिलाड़ी नौ विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती जैसे खेलों में कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर हैं। वहीं, मल्लखंब और कबड्डी को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है।

ग्राम गिधली बसना हर घर जल ग्राम के रूप में प्रमाणित

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार प्रदेश के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। यह योजना महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम गिधली में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना ने ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली लाई है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव के लोगों की सुबह की दिनचर्या पानी की समस्या से शुरू होती थी। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए हैंडपंप और पावर पंप पर निर्भर रहना पड़ता था। गर्मी के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी, जब पानी के स्रोत सूखने लगते थे और लोगों को दूर-दूर तक पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। इससे समय और श्रम दोनों की बर्बादी होती थी, महिलाओं को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

परिस्थिति में बदलाव तब आया जब जल जीवन मिशन के तहत गांव में कार्य प्रारंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत लगभग 100.52 लाख रुपये की लागत से एक पानी टंकी का निर्माण किया गया और करीब 4644 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। जिससे गांव के 250 घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए गए।

वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री ने कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 61.82 लाख की लागत से निर्मित रैन बसेरा का किया लोकार्पण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन द्वारा कोरबा स्थित स्व. श्री बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एसईसीएल के सीएसआर मद से 61.82 लाख रुपये की लागत से निर्मित सर्वसुविधायुक्त आश्रयालय का लोकार्पण किया।

कार्यक्रम में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 4.50 करोड़ रुपये की अत्याधुनिक जांच मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि 50 बिस्तर क्षमता वाला क्रिटिकल केयर यूनिट 16.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन है, जो शीघ्र ही पूर्ण होगा। इसी प्रकार कैजुअल्टी भवन के ऊपरी तल पर 100 बिस्तरों वाले नए वार्ड का निर्माण लगभग 3 करोड़ रुपये में जारी है। गर्मी से मरीजों व परिजनों को राहत दिलाने के उद्देश्य से वार्ड तैयार किया गया है। साथ ही सीएसआर एवं डीएमएफ फंड से सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन की खरीद की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसके बाद जिलेवासियों को अत्याधुनिक उपचार सुविधाएँ मिलेंगी। उन्होंने कहा कि नए आश्रयालय (रैन-बसेरा) के शुरू होने से मरीजों के परिजनों को ठहरने में अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पर उपलब्ध हों। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने कहा कि सुशासन की सरकार एवं केबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में कोरबा में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की गई है। इस अवसर पर सभापति श्री नूतन ठाकुर तथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन डॉ. के.के. सहारे उपस्थित रहे।

अस्पताल में 83 एयर कंडीशनर लगाए जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि 40 बिस्तरों की क्षमता वाला आई वार्ड लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से जल्द प्रारंभ किया जाएगा। नवजात शिशुओं हेतु 6 बिस्तरों का विशेष

हर घर नल से बदली ग्रामीणों की जिंदगी महिलाओं को मिली बड़ी राहत

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 'हर घर नल से जल' योजना का प्रभाव अब व्यापक रूप से दिखाई देने लगा है। इस पहल ने न केवल पेयजल की समस्या का समाधान किया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया है। सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़ौली इसका एक उदाहरण है, जहां अब प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। पहले गांव के लोगों, विशेषकर महिलाओं को दूर-दराज के स्रोतों जैसे कुएं और हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था। इसमें समय और श्रम दोनों अधिक लगते थे, साथ ही दूषित पानी के कारण बीमारियों का खतरा भी बना रहता था। अब घर-घर नल कनेक्शन मिलने से इन समस्याओं का समाधान हो गया है।

ग्राम पंचायत पड़ौली की निवासी श्रीमती देवराजो यादव बताती हैं कि पहले उनके दिन का बड़ा हिस्सा पानी लाने में ही बीत जाता था। 'हर घर नल से जल' योजना लागू होने के बाद अब उनके घर में ही स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है, जिससे दैनिक जीवन काफी आसान हो गया है। अब वे अपने परिवार, बच्चों की पढ़ाई, खेती और आजीविका से जुड़े अन्य कार्यों के लिए अधिक समय दे पा रही हैं। इससे न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।देवराजो यादव सहित ग्रामवासियों ने इस सकारात्मक बदलाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य में जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है, जिससे लोगों के जीवन में व्यापक और स्थायी बदलाव आ रहा है।

राजमिस्त्री की बेटी मोनिखा सोनोवाल ने दर्द और आत्म-संदेह को हराकर जीता केआईटीजी वेटलिफ्टिंग गोल्ड

घुटने की चोट के कारण मोनिखा को केआईटीजी छोड़ने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने पहले खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा लिया

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। 'शायद वह अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर व्यस्त होंगे,' मोनिखा सोनोवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वह अपने पिता को फोन लगाने की कोशिश कर रही थीं। कुछ ही क्षण पहले 19 वर्षीय मोनिखा ने यहां जारी पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था और यह खुशखबरी अपने पिता को देना चाहती थीं। उनके पिता पद्मधर सोनोवाल एक राजमिस्त्री हैं, जो चार सदस्यों के परिवार का पालन-पोषण करने के लिए दिनभर कड़ी मेहनत करते हैं। मोनिखा की खेल यात्रा में वे हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। दो बहनों में बड़ी मोनिखा असम के धेमाजी जिले के बटघोरिया पेनबेनी चौक की रहने वाली हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर बसे इस शांत इलाके की दूरी गुवाहाटी से लगभग 425 किलोमीटर है। यहां जीवन शांत और साधारण है, जहां ज्यादातर परिवारों के सपने रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन मोनिखा के लिए वेटलिफ्टिंग हॉल में बजने वाली बारबेल की आवाज एक ऐसे सपने की शुरुआत थी, जो सीमाओं में बंधने को तैयार नहीं था। सीमित संसाधनों के बावजूद खेल के प्रति उनकी जिज्ञासा धीरे-धीरे जुनून में बदल गई, जिसे पड़ोसी राज्य मणिपुर की टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू से प्रेरणा मिली।

और गुरुवार को वही सपना हकीकत में बदल गया, जब उन्होंने घुटने की चोट के बावजूद संघर्ष करते हुए खेलों का पहला वेटलिफ्टिंग स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह जीत उनके वर्षों की मेहनत का परिणाम थी। उनके सफर में एक बड़ा मोड़ दो साल पहले आया, जब उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के नेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (NCOE) ईटानगर में प्रवेश लिया। कचारी जनजाति से आने वाली मोनिखा ने कहा, 'एनसीओई ईटानगर ने मुझे वह सब कुछ दिया, जिसका मेरे जैसे छोटे गांव की खिलाड़ी केवल सपना देख सकती थी—बेहतर ट्रेनिंग, पोषण, मार्गदर्शन और चोट से उबरने की सुविधा। इस सहयोग के बिना यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। 'इसके बाद उनकी प्रगति लगातार होती रही। 2023 में उन्होंने स्कूल नेशनल्स में स्वर्ण पदक जीता। 2024 में ओडिशा के संबलपुर में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता लीग में रजत पदक हासिल किया। 2025 में तेजपुर में राज्य चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और चंडीगढ़ में इंटर-यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में आठवां स्थान प्राप्त किया। हालांकि, इस उपलब्धि का रास्ता आसान नहीं था। पिछले तीन महीनों से मोनिखा अपने दाहिने घुटने की चोट से जूझ रही थीं, जो उन्हें ट्रेनिंग के दौरान लगी थी।

चोट को देखते हुए उनके कोचों ने उन्हें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में हिस्सा न लेने की सलाह दी थी, लेकिन 19 वर्षीय मोनिखा ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और दर्द के बावजूद मैदान में उतरने का फैसला किया। मोनिखा ने कहा, 'मेरे कोच मेरे घुटने को लेकर चिंतित थे और उन्होंने कहा था कि आराम करना बेहतर होगा। लेकिन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जैसे मौके बार-बार नहीं आते। मैं इतने बड़े मंच पर खेलने का अवसर गंवाना नहीं चाहती थी। ' मोनिखा ने आगे कहा, 'मैं लगातार बेहतर बनना चाहती हूं और एक दिन भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूं। यह गोल्ड तो बस शुरुआत है।

सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा प्रक्रिया में तेजी—हजारों प्रकरणों का परीक्षण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति को लेकर विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर परीक्षण कार्य किया जा रहा है। इसमें वर्ष 2022 से पूर्व नियुक्त 10 और जनवरी - फरवरी वर्ष 2022 में नियुक्त 338,मार्च-मई में नियुक्त 572 तथा जून-दिसंबर 2022 में नियुक्त 90 सहायक प्राध्यापकों के प्रकरणों की समीक्षा कर मामलों में निर्णय लिए गए हैं। इस तरह कुल 1010 परिवीक्षाधीन सहायक प्राध्यापकों के संबंध में परीक्षण के बाद 872 सहायक प्राध्यापकों का परिवीक्षा अवधि समाप्ति की अनुशंसा की गई है और 68 सहायक प्राध्यापक को परिभ्रमण में रखा गया है। इसी तरह 70 प्राध्यापकों के गोपनीय प्रतिवेदन में समिति की शर्तों के अनुरूप न होने के कारण परिवीक्षा अवधि में वृद्धि की अनुशंसा की गई है,जिसमे 53 प्राध्यापकों का 1 वर्ष और 17 सहायक प्राध्यापकों का 2 वर्ष शामिल है। विभागीय जानकारी के अनुसार इन सहायक प्राध्यापकों की परीविक्षा अवधि समाप्ति की प्रक्रिया वर्ष 2025 तक पूरी की जानी है। इसके लिए वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, पुलिस सत्यापन, सतत सेवा प्रमाण-पत्र, निष्ठा प्रमाण-पत्र, विभागीय जांच एवं न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित दस्तावेज तथा चल-अचल संपत्ति विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किया गया।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा